https://www.facebook.com/Kamal.Sandesh/ www.kamalsandesh.org @kamalsandeshbjp

कमल संदेश

आसियान के साथ और मजबूत हुए संबंध

वर्ष-12, अंक-23 01-15 दिसम्बर, 2017 (पाक्षिक) ₹20

गुजरात चुनाव

भाजपा का विकासवाद बनाम कांग्रेस का वंशवाद और जातिवाद

मूडीज ने भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग को 'बाउ3' से बढ़ाकर 'बा2' किया

आर्थिक लोकतंत्र का आगाज

मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई काबू में

गुजरात में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की रैलियों और रोड शो की झलकियां

भावनगर चुनावी रैली में श्री अमित शाह का स्वागत करते गुजरात भाजपा अध्यक्ष श्री जीतू वाघाणी

भावनगर में रोड शो के दौरान श्री अमित शाह और श्री जीतू वाघाणी

भावनगर में रोड शो

भावनगर में रोड शो के दौरान उमड़ा जनज्वार

सूरत में शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक का उद्घाटन करते श्री अमित शाह

शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक में उपस्थित प्रतिनिधिगण

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
प्रभात झा

कार्यकारी संपादक
डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक
संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य
सत्यपाल
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
मुकेश कुमार

संपर्क
फोन: +91(11) 23381428

फैक्स
फैक्स: +91(11) 23387887

ई-मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in
mail@kamalsandesh.com
वेबसाइटः www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 भाजपा हमेशा से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 21 नवंबर को गुजरात के भावनगर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से कांग्रेस के जातिवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता के बजाय...

वैचारिकी

मैं और हम 12

श्रद्धांजलि

आनंदन 14

लेख

आर्थिक लोकतंत्र का आगाज 24

बनेगी विकासमाला 26

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को फिक्स्ड कहना कांग्रेस की हताशा 28

अन्य

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी... 11

'प्रधानमंत्रीजी बने देश की आम जनता की आशाओं व आकांक्षाओं ... 17

मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई काबू में 18

भारतीय रेल को 'बिजली ट्रैक्शन ऊर्जा बिल' से 5636 करोड़... 29

भारत की प्रथम 'एयर डिस्पेंसरी' पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित की जाएगी 30

प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए एक करोड़ आवास की कमी... 31

भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने... 32

स्थायी स्तंभ

सोशल मीडिया से 04

पत्र-पत्रिकाओं से 33

स्फुट विचार 33

संगठनात्मक गतिविधियां

15 भाजपा सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियों व प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री...

21 आसियान के साथ और मजबूत हुए संबंध

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 से 14 नवंबर के बीच तीन-दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस...

सरकार की उपलब्धियां

09 मूडीज ने भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग को 'बा3' से बढ़ाकर 'बा2' किया

मूडी की निवेशक सेवा (मूडीज) ने 17 नवंबर को भारत सरकार की स्थानीय और विदेशी...

10 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब से 178 उत्पादों का टैक्स घटा

जीएसटी काउंसिल की गुवाहटी (असम) बैठक में 10 नवंबर को एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया...

प्रकाशक एवं मुद्रकः डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा मुद्रित, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, बी-2, सेक्टर-63, नोएडा (उ.प्र.)-201307 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। सम्पादक- प्रभात झा

twitter

@narendramodi

2014 में जनता ने ऐसा शासन चुना जिसने तय किया है कि दिल्ली से जो पैसा निकलेगा, वो पूरा पैसा गरीब की सेवा में जाएगा।

@AmitShah

नोटबंदी और कालेधन के लिए SIT जैसे बड़े निर्णय देश को कालेधन और भ्रष्टाचार से मुक्त करने की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं।

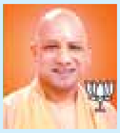

@myogiadityanath

शिक्षा के मामले में भी प्रदेश में अभियान शुरू किया गया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अप्रैल से जुलाई के बीच बेसिक शिक्षा में 1 करोड़ 53 लाख बच्चों ने प्रवेश किया। इन बच्चों की यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूते-मोजे और स्वेटर हम मुहैया करा रहे हैं।

facebook

झारखंड देश का पहला राज्य है जहां CSR काउंसिल का गठन हुआ है, लातेहार के 10 हजार स्कूली बच्चों को आज गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम से फायदा हुआ है।

— रघुबर दास

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को सुशासन में तीसरी रैंकिंग के लिए प्रदेश की जनता और समस्त कर्मचारियों को बधाई, इसीलिए कहते हैं 'सबले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया'।

— डॉ. रमन सिंह

भारत माला योजना के अंतर्गत देश में 35,000 किलोमीटर और बिहार में 1,432 किलोमीटर सड़कें बननी है। पुनपुन से मीठपुर तक 18 किलोमीटर एलिवेटेड सड़क के निर्माण सहित केवल पटना से जुड़े 15 बड़े सड़क प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। जिनके समय बिहार की जर्जर सड़कें मजाक का विषय बनी थीं, उनकी छाती फट रही है।

— सुशील कुमार मोदी

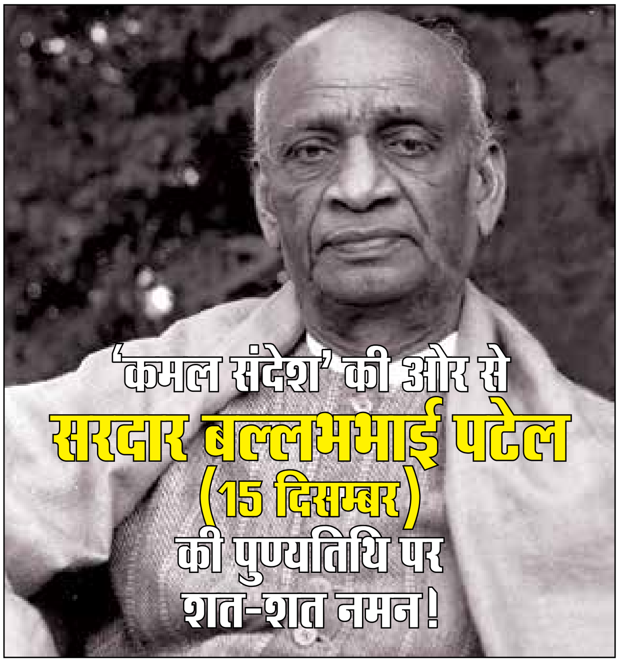

देश के आर्थिक विकास को मिला वैश्विक समर्थन

हर ओर से भारत के लिए अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। लगभग चौदह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद विश्व की प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग में सुधार करते हुए इसे 'सकारात्मक' से 'स्थिर' की श्रेणी में ला खड़ा किया है। यह अब तक की सबसे अच्छी रेटिंग है तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त बदलाव हुआ है, उसकी परिचायक है। इसी प्रकार ओईसीडी की गैलप वर्ल्ड पॉल सर्वे के आधार पर दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि नरेन्द्र मोदी दुनिया की तीसरी सबसे विश्वसनीय सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। इस सर्वे के अनुसार हर चार में से तीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर भरोसा है। प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री एवं इनकी नीतियों तथा सरकार को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। हाल ही में 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' की रिपोर्ट में भारत का 130वें से 100वें स्थान पर छलांग लगाना भाजपानीत सरकार की नीतियों की सफलता को दर्शाता है। साथ ही 'वर्ल्ड इकॉनोमिक रिपोर्ट की स्पर्धात्मकता सूची में 137 देशों में भारत का 40वां स्थान रहा जो अब तक के 71वें स्थान से काफी आगे है। सरकार की आर्थिक नीतियों विशेषकर नोटबंदी और जीएसटी का वैश्विक वित्तीय संस्था स्टानले मॉरगन, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम यांग किम तथा आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टिन लेगार्दे–ने मजबूती से समर्थन किया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन की प्रधानमंत्री की दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति का ही परिणाम है कि कालाधन एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनकी लड़ाई का देश–विदेश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है तथा उनकी संकल्पशक्ति की भूरि–भूरि प्रशंसा हो रही है।

> भारत तेजी से बदल रहा है तथा युवाओं की शक्ति एवं आकांक्षाओं तथा दूरदर्शी नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास के लिए जन–जन में आशाएं एवं अपेक्षाएं तथा सुशासन के लिये समर्पण, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म के मंत्र से 'सबका साथ, सबका विकास' के आधार पर पूरा करने का प्रयास हो रहा है।

अब से ठीक साढ़े तीन वर्ष पूर्व आज की सकारात्मक आर्थिक वातावरण की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। विशेषज्ञों के लिए भी यह अचंभे से कम नहीं कि केवल तीन वर्ष में कोई अर्थव्यवस्था इस प्रकार से पटरी पर आ सकती है और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम मिलाने को तैयार हो सकती है। कौन सोच सकता था कि जो अर्थव्यवस्था कांग्रेसनीत संप्रग सरकार में 'पॉलिसी पैरालिसिस', कुशासन, दिशाहीनता, काला धन, भ्रष्टाचार की चंगुल में फंसा हो, इतनी जल्दी खम ठोकने लगेगी। ऐसा केवल साढ़े तीन वर्ष में ही संभव हो गया, यह पुनः नरेन्द्र मोदी की राजनैतिक दृढ़ता, कड़ी मेहनत एवं दूरदर्शी नेतृत्व का परिचायक है। जिन लोगों ने इन सुधारों का विरोध कर अपने राजनैतिक हित साधने का प्रयास किया, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि नकारात्मक राजनीति के दिन लद चुके हैं। वे 'परफॉरमेंस की राजनीति' के युग में रह रहे हैं और केवल रचनात्मक विपक्ष के रूप में ही अपनी भूमिका तलाश सकते हैं। नोटबंदी और जीएसटी पर देश को भ्रमित करने के उनके प्रयासों से न केवल उनका आधार सिमटा है, बल्कि घोटालेबाजों, भ्रष्टाचारियों एवं कालाधन के कारोबारियों को बचाने वाला उनका चेहरा भी जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। केन्द्र की भाजपानीत सरकार अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव के लिए कृतसंकल्प है तथा 'राष्ट्र प्रथम' के सिद्धांतों पर चलते हुए यह विकास एवं सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने को संकल्पबद्ध है।

देश की राजनीति ने वंशवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद से हटकर 'परफॉरमेंस की राजनीति का शुभारंभ होते देखा है। कांग्रेस, जो कुप्रचार तथा जाति–संप्रदाय के आधार पर समाज को विभाजित कर सत्ता में लौटने का सपना देख रही है, शायद समझ नहीं पा रही कि वह लोगों का विश्वास खो चुकी है तथा भारतीय राजनीति के हाशिये पर पहुंच गई है। जब तक कांग्रेस इस बात को स्वीकार नहीं करेगी कि भारतीय राजनीति अब वंशवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के उसके ब्रांड की राजनीति से बाहर निकल चुकी है, तब तक वह सकारात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पायेगी। भारत तेजी से बदल रहा है तथा युवाओं की शक्ति एवं आकांक्षाओं तथा दूरदर्शी नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहा है। विकास के लिए जन–जन में आशाएं एवं अपेक्षाएं तथा सुशासन के लिये समर्पण, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांस्फॉर्म के मंत्र से 'सबका साथ, सबका विकास' के आधार पर पूरा करने का प्रयास हो रहा है। एक ओर जहां देश के अंदर राजनीति पर विश्वास को पुनर्स्थापित किया गया है, वहीं पूरे विश्व में भारत पर विश्वास बढ़ा है। इससे एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ है जो भारत के लिए अत्यंत उत्साहजनक है। ■

shivshakti@kamalsandesh.org

भाजपा हमेशा से विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 21 नवंबर को गुजरात के भावनगर में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और राज्य की जनता से कांग्रेस के जातिवाद, भ्रष्टाचार और अराजकता के बजाय भाजपा के विकास को जनादेश देने की अपील की। उन्होंने राज्य की जनता से गुजरात में इस बार तीन-चौथाई बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने और कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के विकास की गति को और गति देने के लिए कटिबद्ध हैं। इससे पहले भावनगर पहुंचने पर उन्होंने जनसभा स्थल तक एक भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में श्री शाह के साथ श्री जीतू वाघाणी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री भूपेन्द्र यादव भी उपस्थित थे। इस रोड शो को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह था। जनसभा के बाद श्री शाह की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री जीतूभाई वाघाणी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि 2017 का गुजरात विधानसभा चुनाव दो पार्टियों या दो नेताओं के बीच नहीं, बल्कि जातिवाद एवं परिवारवाद और श्री नरेन्द्र मोदी के विकासवाद के बीच है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आंदोलनों को आउटसोर्स कर गुजरात को एक बार फिर से जातिवाद के चंगुल में फंसाना चाहती है। भावनगर की धरती से उन्होंने गुजरात की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि यह निर्णय आपको लेना है कि कांग्रेस के जातिवाद के साथ जाना है या भारतीय

जनता पार्टी के विकासवाद के साथ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समग्र राष्ट्र को जातिवाद के चंगुल से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अर्थतंत्र को मजबूत किया है, देश की सीमा की सुरक्षा को सुदृढ़ किया है और देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, एवं महिलाओं के लिए कल्याण की अनगिनत योजनायें चलाई हैं और इसे नीचे तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि मोदीजी के तीन साल के कार्यकाल में गुजरात की लगभग सभी समस्याओं का समाधान हुआ है। उन्होंने कहा कि गुजरात में न वंशवाद चलेगा, न जातिवाद चलेगा - गुजरात में केवल विकासवाद चलेगा, यही गुजरात की आम जनता की आवाज है।

श्री शाह ने कहा कि चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन कांग्रेस किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, यह किसी को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह किस मुद्दे पर गुजरात में चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित जितने भी कांग्रेस नेता गुजरात आये हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करने के अलावा कोई और बात ही नहीं की है, ऐसा लगता है कि मोदी-विरोध के अलावा कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सर्वांगीण विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती आई है। उन्होंने कहा कि हमने हमेशा समाज के हर वर्ग की भलाई, दलितों, पिछड़ों एवं आदिवासियों के उत्थान, राज्य के सर्वांगीण विकास, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति, क़ानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार और सीमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि आज भावनगर की जनता ने विकासवाद के प्रति जो अपना अगाध प्यार जताया है, यही गुजरात की जनता का कांग्रेस को जवाब है।

श्री शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को स्थिरता देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने गुजरात को कर्फ्यू-मुक्त बनाया है और राज्य को अंधेरे से दूर करने का काम किया है। उन्होंने गुजरात की जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो गुजरात में एक साल के 250 दिनों तक कर्फ्यू लगाए रखती थी, क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जिसके समय राज्य में क़ानून-व्यवस्था बदहाल और चरमराई हुई थी या फिर ऐसी सरकार चाहिए जिसने गुजरात को लॉ एंड ऑर्डर और कर्फ्यू की समस्या से निजात दिलाकर विकास पर देश का अव्वल राज्य बनाया।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में लगातार गुजरात के साथ अन्याय होता रहा, सरदार साहब के साथ अन्याय होता रहा, उन्हें भारत रत्न देने में देरी की गई और संसद में उनका तैल-चित्र तक नहीं लगने दिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक नर्मदा परियोजना को लटकाए रखा, डैम के दरवाजे लगाने तक को मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के 14 दिनों में ही श्री नरेन्द्रभाई मोदी ने डैम के दरवाजे लगाने को मंजूरी दे दी और हाल ही में नर्मदा योजना को भी राष्ट्र को समर्पित कर दी गई। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने तीन साल की अवधि में ही गुजरात के लिए जो विकास के कार्य किये हैं, वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के तीन साल की अवधि में गुजरात को बुलेट ट्रेन की सौगात मिली, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, रो-रो फेरी सेवा की शुरुआत हुई और 2500 किलोमीटर हाइवे का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुरजात को क्रूड ऑयल की रॉयल्टी ग्रांट भी रोक दी थी, जबकि

अब गुजरात को हर वर्ष रॉयल्टी ग्रांट के लगभग 8,000 करोड़ रुपये मिला करेंगे।

श्री शाह ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात को पर्यटन सेंटर समझ लिया है। राहुल गांधी गुजरात आयें, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन राहुल गांधी को गुजरात की जनता को हिसाब देना चाहिए कि आखिर क्यों कांग्रेस ने गुजरात के साथ लगातार अन्याय किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 सालों तक सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार सत्ता में रही, राहुल गांधी को इस बात का हिसाब देना चाहिए कि इस दौरान कांग्रेस ने गुजरात के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में गुजरात को सेन्ट्रल टैक्स के रूप में केवल 43,345 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जबकि मोदी सरकार के दौरान 14वें वित्त आयोग में गुजरात को 1,22,453 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग में ग्रांट इन ऐड के तौर पर

राहुल गांधी गुजरात आयें, इससे हमें कोई ऐतराज नहीं है लेकिन राहुल गांधी को गुजरात की जनता को हिसाब देना चाहिए कि आखिर क्यों कांग्रेस ने गुजरात के साथ लगातार अन्याय किया। उन्होंने कहा कि केंद्र में 10 सालों तक सोनिया-मनमोहन की कांग्रेस-नीत यूपीए सरकार सत्ता में रही, राहुल गांधी को इस बात का हिसाब देना चाहिए कि इस दौरान कांग्रेस ने गुजरात के लिए क्या किया।

गुजरात को 8,486 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि 14वें वित्त आयोग में ग्रांट इन ऐड के रूप में गुजरात के लिए 17,962 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में भी 839 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जब केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तब गुजरात को विकास के लिए केवल 63,346 करोड़ रुपए मिलते थे। आज जब केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब गुजरात को 1,58,377 करोड़ रुपये मिल रहे हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को गुजरात में आकर विरोध की राजनीति बंद करनी चाहिए और इस बात का जवाब गुजरात की जनता को देना चाहिए कि उन्होंने नर्मदा योजना को क्यों लटकाए रखा, इसकी ग्रांट मंजूर क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 1995 के बाद से गुजरात की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि 1995 की तुलना में से पहले और आज के गुजरात में कृषि क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट करते हुए श्री शाह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी गुजरात ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि

मूंगफली, फल, सब्जी, कपास और मसाले के उत्पादन में भी काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अनाज के उत्पादन भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि नर्मदा का पानी सौराष्ट्र और बोटाद तक पहुंचा है।

श्री शाह ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर की आज की वर्तमान स्थिति किसकी देन है? उन्होंने कहा कि जब उरी में कायरतापूर्ण तरीके से पाक प्रेरित आतंकवादियों के द्वारा हमारे सोये हुए जवान को शहीद कर दिया गया, लेकिन इस बार केंद्र में कांग्रेस की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेन्द्र मोदी सरकार थी। हमने 10 दिन में ही पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और हमारे वीर जवानों की शहादत का बदला लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री पी चिदंबरम कहते हैं कि कश्मीर में आजादी के नारे लगते है तो इसमें गलत क्या है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे पी चिदंबरम के इस बयान का समर्थन करते हैं? रोहिंग्या मुद्दे पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता पी चिदंबरम और शशि थरूर कहते हैं कि रोहिंग्या को भारत में शरण मिलनी चाहिए, क्या भारत की सुरक्षा के साथ कहीं पर भी समझौता होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस विषय की गंभीरता की थोड़ी सी भी समझ है कि नहीं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या मुद्दे पर अपने नेताओं के बयान पर कांग्रेस पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चाहे देश के विकास की बात हो, सीमाओं को सुरक्षित करने की बात हो या दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि करने की बात हो, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर मोर्चे में सफलता के नए आयाम स्थापित किये हैं। उन्होंने गुजरात की जनता से करबद्ध निवेदन करते हुए कहा कि आप भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाइये और 150 से अधिक सीटें पर भाजपा को विजयी बना कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों को मजबूत कीजिये। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता का भाजपा को मिल रहे अपार प्यार और अभूतपूर्व समर्थन से मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 150 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी और जीत के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। ■

मूडीज ने भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग को 'बा3' से बढ़ाकर 'बा2' किया

मूडी की निवेशक सेवा (मूडीज) ने 17 नवंबर को भारत सरकार की स्थानीय और विदेशी मुद्रा जारीकर्ता रेटिंग को उन्नत करते हुए बा3 (Baa3) से बा2 (Baa2) किया और रेटिंग के आउटलुक को बदलते हुए सकारात्मक से स्थिर की श्रेणी में कर दिया। भारत की क्रेडिट रेटिंग में 13 साल बाद यह सुधार हुआ है। भारत की स्वायत्त क्रेडिट रेटिंग में अंतिम सुधार जनवरी 2004 में बा3 (बा1 से) किया गया था।

भारत सरकार ने इस सुधार का स्वागत किया है और साथ ही विश्वास जताया है कि मूडीज के इस कदम से भारत सरकार द्वारा किए गए प्रमुख आर्थिक और संस्थागत सुधारों को मान्यता मिली है। इन सुधारों के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करना; एक सही मौद्रिक नीति का ढांचा तैयार करना; सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए उपाय और अर्थव्यवस्था में औपचारिकता और डिजिटलीकरण (जेएएम एजेंडा) लाने के लिए किए गए कई उपाय; विमुद्रीकरण, "आधार" प्रणाली पर आधारित बायोमेट्रिक खाता तथा लाभ का सीधा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के जरिए संबंधित व्यक्ति के खाते में हस्तांतरण।

मूडीज ने स्थिरता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी मान्यता दी है जिसमें मुद्रास्फीति में कमी, घाटे में गिरावट और विवेकपूर्ण बाह्य संतुलन तथा सरकार के राजकोषीय समेकन कार्यक्रम शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा वर्ष 2013-14 में सकल घरेलू उत्पाद का 4.5 प्रतिशत से कम होकर वर्ष 2016-17 में 3.5 प्रतिशत और सामान्य सरकार ऋण पर भी गंभीर प्रभाव हुए हैं। सरकार मध्यावधि में राजकोषीय समेकन जारी रखने का इरादा रखती है।

मूडीज ने अपने बयान में कहा कि रेटिंग में सुधार देश की सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों, उनका अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ रहा है उन आधारों पर लिया जाता है। मूडीज ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ समय में इन कदमों को उठाया है, मोदी सरकार सरकारी कर्ज को भी कम करने की ओर कदम उठा रही है।

मूडीज ने कहा कि सरकार ने जिस तरह के कदमों को उठाया है, उससे सरकारी कर्ज के वृद्धि का जोखिम कम हो गया है। रिपोर्ट का कहना है कि सरकार अभी कार्यकाल के बीच में है, यानी और भी बढ़े फैसलों की संभावना है। सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जा रहे हैं उनसे व्यापार, विदेशी निवेश आदि की स्थिति भी बदलेगी।

मूडीज ने रिपोर्ट में कहा है कि भारत के द्वारा जिस तरह के आर्थिक सुधार के लिए फैसले लिए गए हैं, उससे दुनिया चौंक गई है। जीएसटी के कारण देश में अंतर्राज्यीय व्यापार में काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा आधार, डॉयरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर स्कीम जैसे सुधार, नॉन परफॉर्मिंग लोन और बैंकिंग सिस्टम में सुधार हुआ है।

मूडीज ने यह भी कहा कि मोदी सरकार के द्वारा जो सुधार किए गए हैं, उनका असर लंबे समय के बाद दिखेगा। मूडीज का अनुमान है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ मार्च 2018 तक 6.7 फीसदी होगी। वहीं अनुमान है कि 2019 तक जीडीपी एक बार फिर 7.5 फीसदी तक पहुंचेगी। ■

आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया: अरुण जेटली

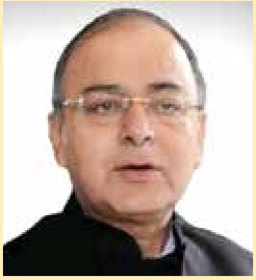

मूडीज की इस नई रेटिंग पर वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा कि आर्थिक सुधार लागू करने के बाद मूडीज ने रेटिंग में सुधार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने जो कदम उठाए हैं उन सभी कदमों का नतीजा है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैसले की मदद से भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक डिजिटल बनाने में मदद की, जिसे हमें आज दुनिया भर में मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा कि मूडीज रैंकिंग से एक अंतरराष्ट्रीय मान्यता स्वीकार हुई है। श्री जेटली ने कहा कि देश में जितने परिवर्तन आए हैं वह सभी एक दिशा में थे।

28 फीसदी के जीएसटी स्लैब से 178 उत्पादों का टैक्स घटा

आम लोगों को भारी राहत

जीएसटी काउंसिल की गुवाहटी (असम) बैठक में 10 नवंबर को एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। काउंसिल ने 178 सामानों को 28 फीसदी के जीएसटी स्लैब से हटाकर 18 फ़ीसदी के कर दायरे में ला दिया। गौरतलब है कि पहले 228 सामान पर 28 फीसदी टैक्स लगता था, अब बस 50 सामान इस स्लैब में रह जाएंगे। यानी करीब 80 फीसदी चीजों को 18 फीसदी के स्लैब में लाया गया। दरअसल, दरें तय करने वाली (फिटमैंट) समिति ने 28 प्रतिशत के स्लैब में आने वाली वस्तुओं की संख्या को घटाकर 62 करने की सिफारिश की थी, जबकि कौसिंल ने इसमें वस्तुओं की संख्या को और घटाकर 50 कर दिया।

इस फैसले के बाद सभी तरह की च्युइंगम, चॉकलेट, फेशियल मैकअप तैयारी के सामान, शैविंग और शैविंग के बाद काम आने वाले सामान, शैंपू, डियोडोरेंट, कपड़े धोने के डिटरजेंट पाउडर व ग्रेनाइट और मार्बल पर अब 18 प्रतिशत दर से जीएसटी लगेगा।

साथ ही कई दूसरी चीजों पर भी जीएसटी की दर कम की गई। काउंसिल ने 6 उत्पादों पर 18 फ़ीसदी जीएसटी को घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया। आठ उत्पादों पर 12 फ़ीसदी जीएसटी को घटाकर पांच फ़ीसदी किया गया। इतना ही नहीं, छह उत्पादों पर 5 फ़ीसदी जीएसटी को घटाकर शून्य कर दिया गया। जीएसटी काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम के तहत कारोबार करने वाले लोगों को काफी राहत दी। अब 1 फीसदी का टैक्स केवल टैक्सेबल आइटम पर ही लगाया जाएगा।

गौरतलब है कि देश में नई जीएसटी प्रणाली का कार्यान्वयन एक जुलाई से किया गया है। इसमें पांच कर स्लैब 0 प्रतिशत, पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत व 28 प्रतिशत रखे गए हैं।

बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने कहा, "इन नए टैक्स रेट को 15 नवंबर से लागू किया जाएगा। केन्द्र और राज्य सरकारें इसके लिए जरूरी नोटिफिकेशन जारी करेंगी।" श्री जेटली ने कहा, "इलेक्ट्रिक गुड्स, सैनिटरी फिटिंग्स, डिटरजेन्ट्स, मार्बल फ्लोरिंग, टायलेटरीज को भी 18% के स्लैब में लाया गया है।"

दरअसल, ये तय किया गया कि 28 फीसदी की स्लैब में सेस वाले आईटम जैसे लग्जरी और सिन गुड्स, एयरक्राफ्ट और यॉट के पार्ट्स जैसे सामानों को छोड़कर सभी को हटा दिया जाए। हालांकि, माना जा रहा है कि आम लोगों को सबसे बड़ी राहत रेस्टोरेंट के खाने को लेकर मिली है, जिसकी अब सिर्फ एक दर 5 फीसदी रखी गई है। श्री जेटली ने कहा, "जो भी ग्राहक रेस्टोरेन्ट जाएगा, उसको अब 18% के बजाय 5% टैक्स देना पड़ेगा। होटलों पर टैक्स दरें-अभी नॉन एसी होटलों, रेस्त्रां में 12 फीसदी व एसी होटलों में खाने पर 18 फीसदी जीएसटी लिया जाता था। अब यह एक समान 5 फीसदी लिया जाएगा। चूंकि होटल पूर्व में दी गई इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ ग्राहकों को नहीं देते थे, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया है।

जीएसटी काउंसिल के इस निर्णय पर बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कौंसिल ने 28 प्रतिशत के सर्वाधिक कर दर वाले स्लैब में वस्तुओं की संख्या को घटाकर सिर्फ 50 कर दिया है जो कि पहले 228 थी। श्री मोदी ने कहा कि फिटमैंट समिति ने इसमें वस्तुओं की संख्या घटाकर 62 करने की सिफारिश की थी, जबकि जीएसटी कौसिंल ने इससे भी आगे बढ़कर 12 और वस्तुओं को इसके दायरे से हटाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस बात पर सहमति थी कि 28 प्रतिशत श्रेणी में केवल अहितकर व गैर जरूरी सामान ही होंगे। श्री मोदी ने कहा कि जीएसटी कौंसिल के आज के फैसले का राजस्व पर असर 20,000 करोड़ रुपए सालाना होगा।

मार्च तक जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 भरने से मुक्ति

जीएसटीएन काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग के नियमों में बड़ी छूट दी है। जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर डेढ़ करोड़ रुपए से कम है, उन्हें जीएसटीआर-2 और जीएसटीआर-3 फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसे व्यापारी मार्च, 2018 तक हर तिमाही में सिर्फ एक बार जीएसटीआर-1 के रूप में अपना रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। सभी कारोबारियों को जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा अगले साल मार्च तक मिलती रहेगी। फिलहाल यह सुविधा सिर्फ दिसंबर तक ही थी। ■

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर को जन उपभोग की अनेक वस्तुओं की जीएसटी दरों में भारी कटौती करने के तुरंत पश्चात्, जीएसटी के अंतर्गत राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (एनएए) के अध्यक्ष और तकनीकी सदस्यों के पदों के सृजन के लिए अपनी मंजूरी दी। इस मंजूरी से इस शीर्ष निकाय की तत्काल स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वस्तु एवं सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ अंतिम उपभोक्ता तक कीमतों में कटौती के माध्यम से पहुंच पाए।

भारत सरकार के सचिव स्तरीय एक वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र और/या राज्यों से चार तकनीकी सदस्यों वाले इस राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण की स्थापना की इस दिशा में एक और प्रयास है, जो उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करेगा की सरकार वस्तु एवं सेवाओं की कम कीमतों के संदर्भ में जीएसटी के कार्यान्वयन के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए सभी संभव कदम उठाने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

गौरतलब है कि 14 नवंबर 2017 की अर्द्ध रात्रि से लागू जीएसटी की दरों में 178 वस्तुओं के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है। अब केवल ऐसी 50 वस्तुएं ही रह गईं है जिन पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसी तरह अनेक वस्तुओं में भी जीएसटी की दरों में 18 से 12 प्रतिशत की कटौती की गई है और इसी तरह कुछ वस्तुओं को जीएसटी से पूर्ण रूप से छूट दे दी गई है।

जीएसटी कानून में उल्लिखित मुनाफारोधी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करती है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी की घटी हुई दरों का पूर्ण लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

जीएसटी कानून में उल्लिखित मुनाफारोधी उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत ढांचे की व्यवस्था करती है कि वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट और जीएसटी की घटी

हुई दरों का पूर्ण लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे। इस संस्थागत ढांचे में एनएए, एक स्थायी समिति, प्रत्येक राज्य में छानबीन समितियां और केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) में सेफ गार्डस महानिदेशालय शामिल हैं।

ऐसे प्रभावित उपभोक्ता जो ऐसा महसूस करते हैं कि वस्तुएं या सेवाएं खरीदने पर उन्हें जीएसटी की कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिल रहा है तो वे अपने संबंधित राज्य में छानबीन समिति के समक्ष राहत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यद्यपि मुनाफाखोरी की स्थिति में अखिल भारतीय स्तर पर बृहत जन-उपभोग की वस्तु से संबंधित मुनाफाखोरी की स्थिति में आवेदन सीधे स्थायी समिति को दिया जा सकता है। प्रथम दृष्टया विचार बनाने के पश्चात् इसमें मुनाफाखोरी का एक घटक है, तो स्थायी समिति मामले की विस्तृत जांच के लिए सैफ गार्डस महानिदेशालय (सीबीईसी) को भेज सकती है, जोकि अपनी जांच रिपोर्ट एनएए को भेजेगी।

यदि एनएए यह पुष्टि करती है कि मुनाफाखोरी विरोधी उपायों को लागू करने की आवश्यकता है तो इसे आपूर्तिकर्ता/संबंधित व्यवसाय को उसकी कीमत घटाने या वस्तुओं या सेवाओं पर लिए ये गैर कानूनी लाभ को ब्याज सहित उपभोक्ता को लौटाने का आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यदि गैर-कानूनी लाभ को उपभोक्ता तक नहीं पहुंचाया जा सकता तो इसे उपभोक्ता कल्याण निधि में जमा करने का आदेश दिया जा सकता है। बहुत गभीर स्थिति में, एनएए चूककर्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर जुर्माना लगा सकती है और जीएसटी के अंतर्गत उसका पंजीकरण भी रद्द कर सकती है। एनएए का गठन उपभोक्ताओं का विश्वास बढाएगा, क्योंकि विशेष रूप से जीएसटी की दरों में हाल ही में की गई कटौती और सामान्य रूप से जीएसटी के लाभ उन तक पहुंचेंगे। ■

मैं और हम

| दीनदयाल उपाध्याय |

गतांक का शेष

साध्य से ही साधन की महत्ता है

'मैं' और 'हम' का यही अंतर है। महाभारत का उदाहरण लें। महाभारत में कहा गया है कि 'यतो धर्मस्ततोजयः' यानी जहां धर्म है, वहीं विजय है। तब लोग एक प्रश्न करते हैं कि महाभारत के युद्ध में कौरवों के जितने प्रमुख सेनापति थे, सब चालाकी से मारे गए। भीष्म को मारने के लिए शिखंडी को खड़ा किया गया। द्रोणाचार्य को युद्ध में समाप्त करने के लिए युधिष्ठिर ने झूठ बोला। कर्ण तब मारा गया, जब वह अपने रथ का पहिया उठाने का अर्जुन से अवसर मांग रहा था। जयद्रथ की मृत्यु का कारण सूर्य का बादलों में छिपना और प्रकट होना बताया जाता है। दुर्योधन की मृत्यु तो कमर के नीचे गदा मारने से ही भीम के हाथों हुई। इसके आधार पर पूछा जा सकता है कि पांडवों की जीत के लिए ये सब जो कार्य हुए क्या उन्हें धर्मानुकूल कहा जाएगा? पांडवों ने छल किया। फिर भी 'जहां धर्म वहां जय' की घोषणा वेदव्यास करते हैं तो क्या यह परस्पर विरोधी बात नहीं है? क्या धर्म के नाम पर अधर्म नहीं हुआ? इसका उत्तर खोजने पर हमें विदित होगा कि कौरव और पांडव पक्ष के बीच एक बड़ा मूलगामी अंतर था। कौरव पक्ष का प्रत्येक योद्धा व्यक्तिवादी था। इसलिए अनर्थ का साथ दे रहा था।

समाज के हित में व्यक्तिगत अपमान भी शिरोधार्य

कौरव पक्ष के योद्धा वीर तथा युद्धकुशल थे, किंतु उनका व्यक्तिवादी दृष्टिकोण इसी बात से प्रकट होता है कि उन्होंने सोचा, ''मैंने प्रतिज्ञा की है, शिखंडी के आने के बाद मैं बाण नहीं चलाऊंगा।'' भीष्म पितामह ने यह नहीं सोचा कि वे सेनापति हैं, उन पर सेना का भार है। उन्हें केवल अपनी निजी प्रतिज्ञा की चिंता थी। दूसरी ओर अर्जुन ने जब इस प्रकार का अपना व्यक्तिवादी दृष्टिकोण बताकर शस्त्र रखने की बात कही तो भगवान् कृष्ण ने उन्हें धर्म का रहस्य बताया कि तू यदि अपने तक सोचता है तो व्यर्थ सोचता है। अर्जुन ने 'मैं' को छोड़ा और 'हम' को स्वीकार किया। भीष्म पितामह ने न अपने पक्ष का, न समाज का, किसी का भी विचार नहीं किया। केवल 'मैं' का विचार मात्र किया। इधर भगवान् कृष्ण ने भी महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी। फिर भी जब अवसर ऐसा ही आ गया कि उन्हें शस्त्र ग्रहण करने पड़े तो उन्होंने आगा-पीछा नहीं किया। समष्टि के हित के लिए उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहा जाएगा? धर्मराज युधिष्ठिर ने भी उनका कहना माना और समष्टि की मांग के समक्ष उन्होंने अपना रथ थोड़ा नीचा कर लिया। उधर द्रोणाचार्य को पुत्र का मोह था। वे पुत्र-वध का समाचार पाकर शस्त्र छोड़ बैठे।

कर्ण ने तो सूर्य द्वारा प्रदत्त अपने कवच-कुंडल भी इंद्र को दे दिए। यद्यपि सूर्य ने चेतावनी दी थी कि कवच-कुंडल न देना। किंतु कर्ण को अपनी दानवीरता का ध्यान था। उसने सबका विचार नहीं किया। इधर कुंती ने आवश्यकता पड़ने पर जाकर कर्ण को बता दिया कि वह उसका ही पुत्र है। कुंती जब कुंवारी थी, तब कर्ण का जन्म हुआ था। यह बात बताने में कुंती को कितना अपमान सहना पड़ा, किंतु समष्टि के लिए उसने न केवल यह बात घोषित की, वरन् अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव पर कर्ण बाण नहीं चलाएगा, यह वचन भी कुंती ने प्राप्त कर लिया। उधर भीष्म की मृत्यु का रहस्य किसी को पता नहीं था, किंतु द्रौपदी ने जाकर जब पूछा तो भीष्म ने बता दिया कि शिखंडी के सामने आने पर वे युद्ध करना बंद कर देंगे। भीष्म ने यह नहीं सोचा कि सेनापति का ऐसा करना सबके हित में नहीं है, किंतु उन्हें सबका नहीं, अपना ही खयाल रहा। इसलिए हम पाते हैं कि कौरव पक्ष में पांडवों के पक्ष की तुलना में एक-से-एक बढ़कर योद्धा और शूरवीर थे, फिर भी उनकी सभी कृतियां अलग-अलग थीं। सबका मिलकर कोई एक कार्य संचालन नहीं था। सबको अपनी-अपनी ही चिंता थी। भीष्म को प्रतिज्ञा की चिंता थी। द्रोणाचार्य को पुत्र का मोह था। दुर्योधन को मात्र अपने राज्य की चिंता थी।

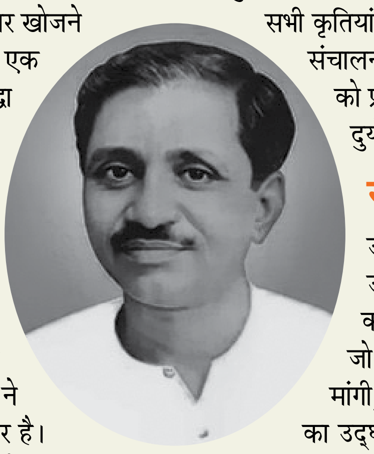

समष्टि के लिए व्यष्टि का त्याग

उधर पांडवों के पक्ष में सबका मिलकर कार्य था। उनमें से प्रत्येक ने अपने-अपने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को छोड़ा। भगवान् कृष्ण के नेतृत्व में एकजुट होकर जो भी कार्य आया, निभाया। कर्ण से भीख मांगना था-मांगी, झूठ बोलने का क्षण आया-बोला, निजी गुप्त रहस्य का उद्घाटन कर स्वयं लांछित होने का प्रश्न आया तो भी चिंता नहीं की, जैसा कृष्ण ने कहा, सब करते रहे। अपना-अपना आग्रह छोड़कर समष्टि के लिए ही कार्यरत हुए। उसका समष्टि का विचार कर कार्य करने का ढंग ही धर्म हुआ और व्यक्तिवादी आधार पर सोचने के कारण कौरवों का पक्ष अधर्म का पक्ष गिना गया। जीत धर्म की हुई, अधर्म की नहीं। यानी समष्टिवाद ही धर्म है। व्यक्तिवाद अधर्म है। राष्ट्र के लिए काम करना धर्म है। राष्ट्र कार्य को साधने के लिए जो कुछ आ पड़े, करना ही उचित है। सच, झूठ, सबकी कसौटी समष्टि का हित है। इसका अर्थ यह नहीं कि धर्मराज ने झूठ बोला, इसलिए हम भी अपने दैनिक जीवन में झूठ बोलने लगे। झूठ बोलना तो खराब गिना ही जाएगा। प्रश्न है कि राष्ट्र का, समष्टि का विचार कर कार्य किया गया है या नहीं? जैसे किसी की हत्या करना पाप है, किंतु युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को

कोई हत्यारा नहीं कहता। शत्रु पर वार करना यह सैनिक का धर्म है। युद्ध में सैनिक रोज हिंसा करता है। उसे परमवीर चक्र देकर हम सम्मानित करते हैं, क्योंकि इस कार्य में वह व्यक्तिवादी ढंग से नहीं सोच रहा। राष्ट्र का विचार कर उसने आचरण किया है, इसलिए अभिनंदनीय है। यही आचरण यदि व्यक्तिगत जीवन में कोई करे तो उसे फांसी की सजा होगी, किंतु युद्ध में शत्रु का विनाश करना राष्ट्ररक्षा का पुनीत कर्तव्य बन जाता है। शत्रु पक्ष में जाकर जासूसी करते समय कितने ही कार्य करने पड़ते हैं। जिन्हें व्यक्ति जीवन में अनुचित ही कहा जाएगा। झूठ बोलना, चोरी करना और कितने ही प्रकार के कार्य करके शत्रु पक्ष के भेद लाने होते हैं। किंतु चूकि ये कार्य समष्टि के हित का ध्यान रखकर संपन्न किए जाते हैं, इसलिए ये सम्मानित होते हैं। राष्ट्र के लिए की गई चोरी चोरी नहीं रहती, यानी कर्म का महत्त्व इस बात पर है कि किस विचार से किया गया है। यदि समष्टि का विचार कर किया गया तो पुण्यकर्म ही है। समष्टि का विचार कर कार्य करने वाले लोगों की शक्ति ही सामूहिक संगठित शक्ति है। व्यक्तिवादी संगठित शक्ति नहीं बना पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीयता का भाव ही शक्ति का मार्ग है।

व्यक्ति का महत्त्व राष्ट्र से है

यह सामूहिक भाव याने राष्ट्रीयता की वह कसौटी है, जिस पर हमारी प्रत्येक कृति, प्रत्येक व्यवस्था ठीक या गलत गिनी जाएगी। उदाहरणार्थ, प्रजातंत्र में प्राप्त नागरिकों के अधिकारों को ही लें। वोट का अधिकार है। वोट देते समय यदि राष्ट्र का विचार रहा तो धर्म होगा और यदि व्यक्तिगत विचार से प्रेरित होकर संपन्न हुआ तो अधर्म हो जाएगा। राष्ट्रीयता यदि ठीक है तो सब व्यवस्था ठीक गिनी जाएगी और यदि राष्ट्रीयता के विपरीत कार्य हुआ तो श्रेष्ठ व्यवस्था भी गलत सिद्ध होगी। जो लोग राष्ट्रीयता का मखौल उड़ाकर, राष्ट्र के विचारों को तिलांजलि देकर विभिन्न प्रकार के 'वादों' के नारे में उलझते हैं, वास्तव में वे भूल करते हैं। उनके हाथ से कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। समाजवाद, पूंजीवाद, प्रजातंत्र अथवा अन्य कोई भी अधिक-से-अधिक एक रास्ता है, प्रगति का आधार नहीं। व्यक्तिगत, दलगत या वादगत कोई विचार लेकर चलने से प्रगति नहीं हो सकती। राजनीति आखिर राष्ट्र के लिए ही है। यदि राष्ट्र का विचार छोड़ दिया, यानी राष्ट्र की अस्मिता, उसके इतिहास, संस्कृति, सभ्यता को छोड़ दिया तो राजनीति का क्या उपयोग? राष्ट्र का स्मरण कर कार्य होगा तो सबका मूल्य बढ़ेगा। राष्ट्र को छोड़ा तो सब शून्य जैसा ही है। राष्ट्र का विचार लेकर आगे बढ़े तो एक और एक मिलकर दो नहीं ग्यारह होते हैं। इस आधार पर संगठन करते जाएं तो एक, एक, एक, एक होकर एक हज़ार एक सौ ग्यारह हो जाते हैं। राष्ट्रीयता छोड़ी तो दशमलव लग गया। अब चाहे जितने एक जोड़ते जाएं शून्य घटता ही जाएगा। राष्ट्र के आधार पर ही व्यक्ति की क़ीमत बढ़ती है। राष्ट्र को छोड़ा तो क़ीमत घटती है।

सामूहिक जीवन के इन संस्कारों को मजबूत करना ही प्रगति का मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति 'मैं' और 'मेरा' विचार त्यागकर 'हम' और 'हमारा' विचार करे। अथवा कई बार देखा जाता है कि व्यक्ति कहता है कि राष्ट्र के लिए जान हाज़िर है और जीवन में सब कार्य व्यक्ति का विचारकर ही करता रहता है, इसमें न व्यक्ति का भला है और न समष्टि का। वास्तव में समष्टि के लिए कार्य करना, यानी धर्माचरण करने की भी शिक्षा होती है। उसमें भी संस्कार डालने होते हैं। इन संस्कारों को प्रदान करना ही राष्ट्र का संगठन करना है।

मैं की सार्थकता हम से ही

किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि 'मैं' नाम की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य इतना ही है कि 'मैं' की सार्थकता 'हम' से होती है। शक्तिभाव जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ढलता है, आवश्यक ही होता है। व्यायाम से शरीर बलशाली होता है। संध्या उपासना करने से अंतःकरण को शांति मिलती है, दीर्घायु प्राप्त होती है। व्यक्तिभाव से व्यक्तिशः सेवा-शुश्रूषा करने से ही यह सब हो पाता है। व्यक्ति को निरोग, दीर्घजीवी, हृष्ट-पुष्ट, आनंदित, प्रसन्न, कार्यक्षम, यशस्वी होना ज़रूरी है। जहां व्यक्ति निर्बल होकर निकम्मा हो जाता है, वहां समष्टि की आराधना का पूरा लोप होना स्वाभाविक ही है। इसलिए व्यक्ति के गुण विकसित होने चाहिए। व्यक्ति निकम्मे हों तो समाज की सेवा किस प्रकार करेंगे। यजुर्वेद में भी कहा गया है कि

अन्धंतमः प्रविशन्ति ये असम्पूतिमुपासते।
ततो भूयऽइव ते तमो यथउ सम्पूत्यां रताः।।

यजु. 9740

जो व्यक्तिवाद का अवलंबन करते हैं, वे अधःपतन को प्राप्त होते हैं, परंतु जो समष्टिवाद में रमते हैं, वे उससे भी अधिक नीचे गिरते हैं।

अस्तु भारतीय तत्त्व ज्ञानियों ने 'मैं' और 'हम' को समन्वित करने का विचार रखा है। उनका कहना है-

संभूतिं च विनाश च यस्तद्वेदो भयं छ सह।
विनाशेन मृत्यु तीर्त्वा सष्णुत्यामृतमश्नुते।।

यजु. 11/40

समष्टिवाद और व्यक्तिवाद ये दोनों साथ-साथ रहें, तो लाभदायक होते हैं। व्यक्तिवाद के अनुष्ठान से व्यक्ति के कष्ट दूर किए जाते हैं और समष्टिवाद से अमरत्व की प्राप्ति होती है।

यही 'संभूय समुत्थान' का अर्थ है। संघ बनाकर उठना ही प्रगति का रास्ता है। संघ बनाकर न रहना अर्थात् व्यक्तिशः रहना, व्यक्ति का पृथक रहना असंगठित अवस्था है। इसी का नाम विनाश है, क्योंकि व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है और संघ अजरामर रह सकता है। मानवों का अमरत्व संघ भाव से है और व्यक्ति बिखरा हुआ रहे तो व्यक्ति का नाश निश्चित है। इसलिए व्यक्तियों को गुणवान, शक्तिवान बनना चाहिए और व्यक्तिवाद छोड़कर संघ शक्ति की आराधना करना चाहिए। मनुष्य अमरत्व चाहता है। वह अमरत्व संभूति से ही मिल सकता है। 'संभूत्या अमृतं अश्नुते' संघ से अमरत्व प्राप्त होता है। संघजीवन, सामुदायिक जीवन जीना ही अमरत्व प्राप्त करना है। इस दृष्टि से 'मैं' के वास्तविक रूप 'हम' को ग्रहण करना चाहिए।

— (राष्ट्रधर्म, सितंबर 5, 1956) समाप्त

केरल में रा.स्व.संघ स्वयंसेवक आनंदन की हत्या

केरल में वामपंथी-जेहादी आतंक का खूनी-खेल निरंतर जारी है। एक बार फिर 12 नवंबर को माकपा कार्यकर्ताओं ने त्रिशूर के गुरवायूर इलाके में रा.स्व.संघ के स्वयंसेवक श्री आनंदन की नृशंस हत्या कर दी। श्री आनंदन 23 वर्ष के थे। दरअसल, श्री आनंदन अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी कार में सवार हमलावरों ने उसे टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि श्री आनंदन मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी कार में सवार माकपा कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला किया, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। श्री आनंदन ब्रह्मकुलम इलाके के रहने वाले थे।

केरल में वामपंथी हिंसा का कहर इस तथ्य से साफ स्पष्ट है कि 2001 के बाद से केरल में भाजपा के 120 कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं, जिसमें केवल कन्नूर में ही 84 मारे गए। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री श्री पिनरायी विजयन के पिछले साल सत्ता संभालने के बाद से 16 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है।

इस नृशंस हत्या पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि मैं गुरवायूर में रा.स्व.संघ के युवा स्वयंसेवक श्री आनंदन की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। सीपीएम कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा और ऐसी राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों को संरक्षण अब देश के सामने है। मुख्यमंत्री श्री पिनरायी विजयन को जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में आपराधिक तत्वों पर काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है? श्री शाह ने कहा कि माकपा कार्यकर्ताओं की हिंसा निरंतर जारी है और राष्ट्र यह जानता है कि इन हत्याओं को राजनैतिक संरक्षण भी प्राप्त है। गौरतलब है कि श्री अमित शाह ने पिछले माह केरल में भाजपा एवं रा.स्व.संघ के स्वयंसेवकों की हत्याओं के विरोध में 15 दिनों की जन रक्षा यात्रा निकाली थी।

केरल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री कुम्मनम राजशेखरन ने कहा कि पिनरायी विजयन के पिछले 16 महीने के कम्युनिस्ट शासनकाल में हमने 16 समर्पित कार्यकर्ताओं को खो दिया है। वामपंथी-जेहादी आतंकवाद की कोशिश यह है कि हमारे भावी नेताओं को पनपने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया जाय। साथ ही श्री राजशेखरन ने यह भी कहा कि केरल में जंगलराज को उजागर करने के लिए सभी राष्ट्रवादी और प्रबुद्ध लोगों के सहयोग की जरूरत है। ■

@AmitShah

मैं गुरवायूर में आरएसएस के युवा स्वयंसेवक के आनंद की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करता हूं। सीपीएम कार्यकर्ताओं की लगातार हिंसा और ऐसी राजनीतिक हत्याओं में शामिल लोगों को संरक्षण अब देश के सामने है। मुख्यमंत्री पी विजयन को जवाब देना चाहिए कि उनके शासन में आपराधिक तत्वों पर काबू पाने के लिए क्या किया जा रहा है।

— अमित शाह

भाजपा सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियों व प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम: अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 17 नवंबर को ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी मूडीज द्वारा 13 साल बाद भारत की सॉवरन क्रेडिट रेटिंग्स को बा3 (Baa3) से बढ़ाकर बा2 (Baa2) और रेटिंग आउटलुक को स्थिर से बढ़ाकर सकारात्मक किये जाने का स्वागत करते हुए इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की आर्थिक सुधार की नीतियों व प्रभावी कार्यान्वयन का परिणाम बताया।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक मोर्चे पर लगातार सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रेटिंग में भारत ने 30 स्थान की छलांग लगाई और अब मूडीज ने 13 साल में पहली बार भारत की रेटिंग्स में सकारात्मक बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी के जरिये अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने और लेस इकॉनमी जोन में बदलने के प्रयासों की मूडीज ने जमकर सराहना करते हुए कहा है कि भारत में आर्थिक और सांस्थानिक सुधारों की वजह से अर्थतंत्र में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ी है, जिसके चलते भारत की रेटिंग में सुधार किया गया है, यह इस बात का द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है।

नोटबंदी और जीएसटी के जरिये अर्थव्यवस्था को पारदर्शी बनाने और लेस इकॉनमी जोन में बदलने के प्रयासों की मूडीज ने जमकर सराहना करते हुए कहा है कि भारत में आर्थिक और सांस्थानिक सुधारों की वजह से अर्थतंत्र में वृद्धि की संभावनाएं बढ़ी है, जिसके चलते भारत की रेटिंग में सुधार किया गया है, यह इस बात का द्योतक है कि हमारी अर्थव्यवस्था सही दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मूडीज ने भारत की रेटिंग 13 साल बाद अपग्रेड की है, इससे यह स्पष्ट है कि सोनिया गांधी-मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने 10 सालों में देश के आर्थिक ढांचे को किस तरह से तहस-नहस कर दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के दौरान अर्थव्यवस्था के हर मापदंड नीचे की ओर जा रहे थे और भविष्य को लेकर कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार 10 वर्षों तक इस तरह से चली कि हर जगह यही चर्चा होती थी कि सोनिया-मनमोहन की सरकार पॉलिसी पैरालिसिस से ग्रस्त है।

श्री शाह ने कहा कि मूडीज ने इस बात की तस्दीक की है कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जैसे सुधार से राज्यों के बीच व्यापार की बाधा को हटाकर उत्पादकता बढ़ाएंगे, साथ ही मौद्रिक नीति ढांचे में सुधार, बैंकों के अटके पड़े लोन की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम और नोटबंदी, बायोमीट्रिक व्यवस्था के लिए आधार का विस्तार एवं डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के जरिए सब्सिडी की रकम सही व्यक्ति तक पहुंचाने जैसी कवायदें अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियां ठीक करने के लिए की गई हैं। उन्होंने कहा कि मूडीज ने भी आशा व्यक्त की है कि मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों के लिए उठाये गए अन्य क़दमों का असर निकट भविष्य में जल्द ही दिखने को मिलेगा।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मूडीज ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत की आर्थिक विकास दर जल्द ही 7.5 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी और लॉन्ग टर्म में भारत की विकास की संभावना बा रेटिंग वाले ज्यादातर देशों से बहुत ज्यादा है और विश्वास व्यक्त किया है कि मोदी सरकार की आर्थिक सुधार नीतियों से कारोबारी माहौल में सुधार होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, अधिक निवेश आयेगा और भारत उच्च विकास पथ पर अग्रसर होगा।

श्री शाह ने कहा कि देश ने कांग्रेस की सरकार के समय एक दौर ऐसा भी देखा है जब अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत

को एक नए ग्रुप का हिस्सा बनाया गया था, इस ग्रुप का नाम था- फ्रेजाइल फाइव। उन्होंने कहा कि इसे ऐसा डेंजरस ग्रुप माना गया था, जिसकी खुद की अर्थव्यवस्था तो एक समस्या थी ही, बल्कि ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी बाधा बन रहे थे, समझ में नहीं आता कि बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों के रहते हुए देश में ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत पहली बार विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार के अंतिम 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए, जब विकास दर 5.7 प्रतिशत या उससे नीचे गिरी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अथक प्रयासों के कारण देश की आर्थिक विकास दर लगातार तीन साल तक 7% से ऊपर रही। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि पिछले तीन वर्षों में 7.5 प्रतिशत की औसत ग्रोथ हासिल करने के बाद इस वर्ष अप्रैल-जून की तिमाही में GDP ग्रोथ में कमी दर्ज की गई, लेकिन यह स्थिति भी आर्थिक सुधारों को सुदृढ़ करने के कारण आई है जो जल्द ही समाप्त हो जायेगी। उन्होंने कहा कि ऐसा केवल पार्टी या सरकार का कहना नहीं है बल्कि मूडीज, वर्ल्ड बैंक और नेमुरा जैसी अंतर्राष्ट्रीय एवं प्रतिष्ठित आर्थिक एजेंसियों ने भी इसकी तस्दीक की है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के हर पैरामीटर में व्यापक सुधार किया है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता महंगाई दर लगातार गिरावट की ओर है, चालू घाटा घट कर जीडीपी का 0.3 फीसदी रह गया है, देश में एफडीआई फ्लो में रिकॉर्ड उछाल आया है और सरकार लगातार फिस्कल कंसॉलिडेशन की राह पर है। उन्होंने कहा कि 2011-12 में यूपीए II के दौरान फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 5.9% था, जो घट कर अब 3.5% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यूपीए सरकार का कार्यकाल ख़त्म होने के समय 2013-14 में भारत का विदेशी मुद्रा भण्डार 294.4 बिलियन डॉलर था, जो वर्तमान में 400 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। उन्होंने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार ने पहली बार 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अथक प्रयासों के कारण भारत निर्माण उद्योग के मामले में दुनिया में छठे स्थान पर पहुंच गया है, पहले हम 9वें स्थान पर थे। उन्होंने कहा कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम कैश के साथ चल रही है, डिमोनेटाईजेशन के बाद कैश टू जीडीपी रेशियो 9% पर आ गया है, जबकि नोटबंदी लागू होने से पहले 12% से ज्यादा हुआ करता था।

श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार के साढ़े तीन सालों में देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, ग्लोबल कंपीटीटिव इंडेक्स में हम कई पायदान ऊपर चढ़े हैं। शुरुआती गिरावट के बाद निर्यात में भी लगातार वृद्धि हो रही है और बिजली उपलब्धता में भी हमें 26 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि पिछला वित्तीय वर्ष कई मायनों में बेमिसाल उपलब्धियों वाला वर्ष रहा, जब भारत में सबसे ज्यादा यूरिया का उत्पादन हुआ, इथेनॉल का उत्पादन हुआ, सबसे ज्यादा घरेलू गैस कनेक्शन वितरित किये गए, सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन हुआ, सबसे ज्यादा विद्युत् उत्पादन हुआ, सबसे ज्यादा पूंजी रेलवे के विकास के लिए दी गई, सबसे ज्यादा राजमार्ग बनाए गए, सबसे ज्यादा तेज गति से ग्रामीण सड़कें बनाई गयी। सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का निर्यात किया गया और सबसे ज्यादा मोटर गाड़ी व टू व्हीलर का उत्पादन हुआ। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू इंडिया की नींव रखने का काम किया है, ताकि हम अपने देश को एक बार फिर से विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर सकें। ■

केन्द्र सरकार ने उद्योग जगत से जीएसटी दर में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को देने की अपील की

जीएसटी परिषद् ने 10 नवम्बर, 2017 को गुवाहाटी में आयोजित अपनी 23वीं बैठक में 178 शीर्षकों या मदों के तहत आने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने की सिफारिश की, जिससे अब 28 प्रतिशत की जीएसटी स्लैब दर में केवल 50 वस्तुएं ही रह गई हैं। इसी तरह अनेक वस्तुओं पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत और कई अन्य वस्तुओं पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। ये सभी परिवर्तन 14 नवम्बर, 2017 की मध्यरात्रि से प्रभावी हो गये। जीएसटी दर में की गई कमी का लाभ उपभोक्ताओं को देना है, जिसके लिए आपूर्तिकर्ताओं को कीमतों में इसी अनुपात में कमी करनी होगी। जीएसटी दरों में कमी से घरेलू मांग और निवेश बढ़ने की उम्मीद है।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की अध्यक्ष सुश्री वनाजा एन.सरना ने सभी प्रमुख एफएमसीजी (तेज खपत वाली वस्तुएं) कंपनियों को पत्र लिखकर उन सभी उत्पादों की एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) में तत्काल संशोधन करने की जरूरत बताई, जिन पर जीएसटी घटाने की घोषणा परिषद ने की है। उन्होंने इन सभी कंपनियों से अपने उत्पादों की संशोधित एमआरपी का व्यापक प्रचार करने का भी अनुरोध किया। सरकार ने उम्मीद जताई है कि उद्योग जगत इससे पहले वित्त मंत्री द्वारा इस बारे में की गई अपील पर तत्काल ध्यान देंगे। ■

'प्रधानमंत्रीजी बने देश की आम जनता की आशाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के प्रतीक'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 16 नवंबर को विश्व की प्रतिष्ठित प्यू रिसर्च सेंटर सर्वे की रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले साढ़े तीन सालों में देश के हर हिस्से और समाज के हर वर्ग में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और लोकप्रियता का यह ग्राफ लगातार ऊपर की ओर ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश की आम जनता की आशाओं व आकांक्षाओं की पूर्ति के प्रतीक बने हैं।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जिस तरह से देश के विकास और गरीब लोगों के कल्याण में बाधक चुनौतियों का सहजता से समाधान करते हैं, उससे देश के जन-जन में प्रधानमंत्री जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास निरंतर और दृढ़ ही होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता धर्म, जाति, क्षेत्र और सीमा से कहीं ऊपर है, वे हिन्दुस्तान के जन-जन के मन में हैं, प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट इस तथ्य को ही प्रमाणित करती है। उन्होंने कहा कि प्यू के सर्वे में तकरीबन 10 में से 9 भारतीयों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है, यह अपने-आप में प्रधानमंत्री जी की अद्भुत लोकप्रियता का परिचायक है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश हर मोर्चे पर कामयाबी का नया इतिहास गढ़ रहा है। चाहे वह आर्थिक सुधारों की बात हो, देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा कवच देने की बात हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, सीमा की सुरक्षा की बात हो, विदेश नीति को एक नई दिशा देने की बात हो, भारतीय संस्कृति को विश्व-पटल पर प्रतिष्ठित करने की बात हो या फिर आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व के सभी देशों को एक साथ लाने की बात हो।

श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, युवा एवं महिलाओं के लिए तीन सालों में 106 लोक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है और इनमें से हर योजना सर्वस्पर्शी और सर्व-समावेशी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश को एक निर्णायक, भ्रष्टाचार-मुक्त और पारदर्शी सरकार देने का काम किया है, इस दौरान हमारे विरोधी भी केंद्र की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले तीन सालों में देश में जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति का अंत हुआ है और पॉलिटिक्स ऑफ़ परफॉरमेंस की शुरुआत हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी है, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में रिकॉर्ड उछाल आया है, फॉरेन रिजर्व में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और नोटबंदी व जीएसटी से पारदर्शी और लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में खुले में शौच से मुक्ति के लिए मुहिम की शुरुआत हुई है। साथ ही, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और स्वच्छता अभियान जैसे सामाजिक समस्याओं को जन-जन का आंदोलन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि स्किल इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और मुद्रा बैंक योजना से युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से देश की गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है। जन-धन योजना और सामाजिक सुरक्षा बीमा से देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है और स्वास्थ्य बीमा व दवाइयों के दाम कम किये जाने से आम जनता को लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसानों की फसल खेत से खलिहान तक सुरक्षित हुई है, स्वायल हेल्थ कार्ड से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, नीम-कोटेड यूरिया से यूरिया की कालाबाजारी बंद हुई है और ई-मंडी से किसानों को अपने फसल के लिए एक नेशनल प्लेटफ़ॉर्म मिला है। उन्होंने कहा कि देश के विकास एवं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने औसतन हर 15 दिन में एक नई योजना की शुरुआत की है। साथ ही इसे समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी प्रबंध किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के इन प्रयासों से पहली बार देश की जनता को यह पता चला है कि देश और समाज का कल्याण करने वाली सरकार किस तरह से काम करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के विकास एवं आम जनता की भलाई के लिए किये गए कार्यों और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का ही परिणाम है कि 2014 के बाद देश में संपन्न हुए लगभग हर चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत हासिल हुई है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज विश्व के किसी भी देश में प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो हजारों-हजार का हुजूम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत के लिए लालायित रहता है। यह हिन्दुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश इसी तरह से सफलता की कहानियां लिखता रहेगा और विश्वगुरु के पद पर एक बार फिर से प्रतिष्ठित होगा। ■

मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ महंगाई काबू में

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 24 अक्टूबर को देश की अर्थव्यवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत हुई है, बल्कि इसमें स्थिरता भी आई है। यहां प्रस्तुत है रिपोर्ट के प्रमुख अंश का दूसरा एवं अंतिम भाग:

विमुद्रीकरण सहित काले धन के विरुद्ध धर्मयुद्ध

काले धन को नियंत्रित करने के लिए ढ़ांचे की निगरानी और समीक्षा के लिए मई, 2014 में गठित काले धन के संबंध में विशेष जांच टीम; (ख) 01 जुलाई, 2015 से लागू किए गए काला धन (अघोषित विदेशी आय और आस्तियां) और टैक्स आरोपण अधिनियम, 2015; (ग) आय घोषणा योजना, 2016; और (घ) 01 नवंबर, 2016 से प्रभावी रूप से लागू किए गए समग्र बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) संशोधन अधिनियम, 2016 जैसी पहलों ने काले धन के सृजन और धारिता के विरुद्ध छेड़े गए युद्ध में सफलता दिलाई। 08 नवंबर, 2016 से प्रभावित उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के विमुद्रीकरण से काले धन पर भारी प्रहार हुआ है।

आवास विकास

सरकार ने अर्थव्यवस्था में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बजट सत्र 2017-18 में विभिन्न उपायों की घोषणा की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सस्ते आवास को अवसंरचना का दर्जा देकर अवसंरचना विकास की गति बढ़ाना, राजमार्ग निर्माण को अधिक आवंटन, तटीय संपर्क पर विशेष ध्यान देना शामिल है। अन्य विकास संवर्धन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैः 50 करोड़ रुपए तक वार्षिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए कम आयकर; मैट क्रेडिट को वर्तमान की 10 वर्षों की बजाए 15 वर्ष की अवधि तक आगे स्थानांतरित करने की अनुमति देना; व्यवसाय करना आसान बनाने को उन्नत बनाने के लिए और उपाय तथा डिजीटल अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से आगे बढ़ाना शामिल है। बजट में भी अधिक कृषि ऋण देने और काफी हद तक रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया।

संस्थागत सुधार

संस्थागत सुधारों में, व्यय का यौक्तिकीकरण और लक्ष्य एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर विशेष जोर देते हुए सार्वजनिक सुपुर्दगी में रिसाव को प्रगामी रूप से समाप्त करना; सुदृढ़ी कारगर वित्तीय समावेषण कार्यक्रम की शुरूआत; अभिशासन और निर्णय लेने में नीतिगत पारदर्शिता लाने के उपाय; डिस्कॉम के लिए उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना (यूडीएवाई) कार्यक्रम; विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदारीकरण; और भारत में बौद्धिक संपदा हेतु भावी

दिशा-निर्देश बनाने के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का अनुमोदन।

व्यवसाय करना आसान बनाना

प्रायोगिक मेक इन इंडिया कार्यक्रम के इर्दगिर्द संपूरक का निर्माण, इसमें व्यवसाय करना आसान बनाने में सुधार लाने के लिए व्यापक उपाय, स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया पहलों के अंतर्गत उभरते उद्यमशील प्रतिभा को प्रोत्साहित करना तथा विज्ञापन एवं वैश्विक अभियान में प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक केंद्र के रूप में भारत के वैश्विक दर्जा में सुधार लाया है। भारत ने एकीकृत भुगतान केंद्र वाले सप्ताह के 24 घंटे एकल पोर्टल पर सभी व्यापार निवेश संबंधी निकासी और अनुपालना उपलब्ध करके व्यापार और निवेशक अनुकूल प्रास्थिति के सृजन के लिए ईबिज मंच शुरू किया है।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति में आमूल-चूल परिवर्तन

सरकार ने 20 जून, 2016 को एफडीआई के क्षेत्र को एकाएक उदार बना दिया, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से रोजगार और नौकरी के सृजन को गति प्रदान करना है। नवम्बर, 2015 में घोषित प्रमुख परिवर्तनों के बाद यह दूसरा प्रमुख सुधार है। अब छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग पर कार्य करेंगे। नीति में शुरू किए गए परिवर्तनों में क्षेत्रीय अंतराल बढ़ाना, स्वतः मार्ग के अंतर्गत अधिक क्रियाकलापों को लाना और विदेशी निवेश के लिए

शर्तों को आसान बनाना शामिल है। इन परिवर्तनों से भारत एफडीआई के लिए विश्व में सबसे अधिक खुला देश बन गया है।

अत्यन्त निर्धन महिलाओं को 3 करोड़ से भी अधिक एलपीजी कनेक्शन

अत्यन्त निर्धनों की सहायता करने तथा उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए विशेषकर महिलाओं के लिए सरकार ने मई, 2016 और जून, 2017 के बीच 3 करोड़ से भी अधिक एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराया है, जो गंदगी भरे पारंपरिक ईंधनों की जगह लेंगे, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसी प्रकार मानवकृत तथा प्राकृतिक आपदाओं के सदमें से गरीब जनता को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री स्वस्थ बीमा योजना के अंतर्गत सितम्बर, 2017 तक कुल 14 करोड़ व्यक्तियों का नामांकन किया गया।

अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) पर बल

सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को नये सिरे से गति प्रदान करने के उद्देश्य से अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि की है। इस वर्ष 21.46 लाख करोड़ रुपए के बजटीय व्यय (पिछले वर्ष की तुलना में 1.2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि) में से, भारत सरकार का कुल व्यय 11.47 लाख करोड़ रुपए (सितम्बर, 2017) से अधिक हो चुका है।

इस अभियान का विशेष जोर ग्रामीण सड़कों, आवासन, रेलवे, विद्युत, राजमार्गों और डिजिटल अवसंरचना सहित महत्वपूर्ण विकास के क्षेत्रों पर है। वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार का पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 3.09 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 31.28 प्रतिशत अधिक है, जिसमें से सितम्बर, 2017 तक 1.46 लाख करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत कार्यों पर खर्च की जा चुकी है। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए पूंजीगत व्यय लक्ष्य 3.85 लाख करोड़ रुपए नियत किया है, जिसमें से सितम्बर, 2017 तक सीपीएसई द्वारा 1.3 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय के खर्च का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है।

रेलवे

रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय हेतु 1,31,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के विपरीत, 50,762 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। मुख्य जोर सुरक्षा को बेहतर बनाने, नई लाइनें बनाने और यात्रियों को सुख-सुविधाएं प्रदान करने के लिए अवसंरचना के उन्नयन पर है।

निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए: नई लाइनें (निर्माण) (4531.93 करोड़ रुपए), गेज बदलना (1842.24 करोड़ रुपए), ईबीआर-भागीदारी (11504.29 करोड़ रुपए), पटरी को डबल करना (4069.60 करोड़ रुपए), यातायात सुविधाएं (517.05 करोड़ रुपए), रोलिंग स्टॉक (8214.11 करोड़ रुपए), पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियां – मुख्य घटक (7781.97 करोड़ रुपए), रोड ओवर/अंडर ब्रिज (1068.09 करोड़ रुपए), पटरियों का नवीकरण (2837.72 करोड़ रुपए), विद्युतीकरण परियोजनाएं (1119.17 करोड़ रुपए), यात्रियों को सुख-सुविधाएं (539.73 करोड़ रुपए), जेवी/एसपीवी में निवेश (1263.52 करोड़ रुपए), महानगरीय परिवहन परियोजनाएं (446.16 करोड़ रुपए) आदि।

सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मार्च, 2019 तक देश में बिजली प्राप्त करने से वंचित रह गए सभी उपभोक्ताओं को कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए सर्वसुलभ विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण की चालू योजना (दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना) के अतिरिक्त है।

सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने और आर्थिक विकास को नये सिरे से गति प्रदान करने के उद्देश्य से अवसंरचना पर सार्वजनिक व्यय में निरंतर वृद्धि की है। इस वर्ष 21.46 लाख करोड़ रुपए के बजटीय व्यय (पिछले वर्ष की तुलना में 1.2 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि) में से, भारत सरकार का कुल व्यय 11.47 लाख करोड़ रुपए (सितम्बर, 2017) से अधिक हो चुका है।

ग्रामीण सड़कें – प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

पीएमजीएसवाई के फेस-I और II को पूरा करने के लिए, भारत सरकार का राज्यों के साथ मिलकर 2017-18 से शुरू करके 03 वर्षों में 88,185 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का प्रस्ताव है। इससे 1,09,302 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा, जिससे 36,434 बस्तियों को लाभ होगा।

इसके अतिरिक्त, 11,725 करोड़ रुपए की लागत की सड़कों का निर्माण 2019-20 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें मौजूदा सड़कों के 5411 किलोमीटर का उन्नयन और 44 एलडब्ल्यूई जिलों में नई सड़कों का निर्माण शामिल है।

पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) – शहरी और ग्रामीण

निर्माण सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए सभी के लिए सार्वभौमिक किफायती आवासन का क्रियान्वयन किया जा रहा है और इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है। पीएमएवाई (शहरी) के अधीन, अगले 03 वर्षों में 1,85,069 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1.2 करोड़ यूनिटों का निर्माण किया जाएगा। पीएमएवाई (ग्रामीण) के अधीन, मार्च, 2019 तक केंद्र और राज्यों द्वारा 126,795 करोड़ रुपए के परिव्यय से 1.02 करोड़ यूनिटों (इस वर्ष 51 लाख यूनिट) का निर्माण किया जाएगा।

भविष्य में अधिक मजबूत आर्थिक विकास

जीडीपी वृद्धि द्वारा मापी जाने वाली अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि ने लगातार सुधार दर्शाया है। पिछले दो वर्षों में 5.9 प्रतिशत की तुलना में 2014-15 और 2016-17 के बीच इसका औसत 7.5 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 के लिए कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 275.7 मिलियन टन होने की आशा है, जो पिछले वर्ष 251.6 मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 9.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2017-18 के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ मौसम के लिए खाद्यान्नों का उत्पादन 134.67 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2016-17 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार खाद्यान्नों का उत्पादन 138.52 टन मिलियन था।

वैश्विक आर्थिक स्थिति में गिरावट के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात की मांग कम होने के बावजूद औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आईआईपी) 2016-17 के दौरान 4.6 प्रतिशत बढ़ा, जबकि 2015-16 में यह वृद्धि 3.3 प्रतिशत (संशोधित आईआईपी श्रृंखला के अनुसार) थी। अप्रैल-अगस्त, 2017 के दौरान सामान्य आईआईपी वृद्धि 2.2 प्रतिशत थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 5.9 प्रतिशत थी। अगस्त, 2017 के दौरान आईआईपी में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो जून में (-)0.2 प्रतिशत तथा जुलाई, 2017 में 0.9 प्रतिशत की वृद्धि से काफी अधिक है। सवारी वाहनों की बिक्री में सितम्बर, 2017 के लिए 11.3 प्रतिशत और अप्रैल-सितम्बर के लिए 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी प्रकार वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री सितम्बर, 2017 में 25.3 प्रतिशत और अप्रैल-सितम्बर, 2017 के लिए 6 प्रतिशत बढ़ी।

वास्तविक जीडीपी वृद्धि

अक्तूबर, 2017 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकलन के अनुसार भारत का विकास 2017 में 6.7 प्रतिशत और 2018 में 7.4 प्रतिशत होने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी पूर्वानुमान लगाया है कि 2022 तक भारत का विकास 8.2 प्रतिशत बढ़ जाएगा। चीन का विकास 2016 में 6.7 प्रतिशत था और क्रमशः 2017 तथा 2018 में 6.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत होने की आशा है। हम आशा करते हैं कि इस तिमाही में दुबारा मजबूत विकास करेंगे और हमारे भावी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों से भी बेहतर होंगे। ■

भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी परियोजनाओं का शुभारम्भ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने 9 नवंबर को दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से कनेक्टिविटी परियोजनाओं की श्रृंखला का उद्घाटन किया। इनमें द्वितीय भैरब और टिटास रेलवे पुल, कोलकाता में चितपुर के अन्तर्राष्ट्रीय रेल यात्री टर्मिनल भी शामिल हैं। उन्होंने कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रेल के परिचालन की शुरुआत की। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज भी नई दिल्ली से इस कार्यक्रम में शामिल हुईं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा शुरू से ही मानना रहा है कि पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ सही मायने में पड़ोसियों जैसे संबंध होने चाहिए। जब मन किया तो बात होनी चाहिए, विजिट्स होने चाहिए। इस सबमें हमें प्रोटोकॉल के बंधन में नहीं रहना चाहिए। कुछ समय पहले हमने साउथ एशिया सैटेलाइट के लांच के समय इसी प्रकार वीडियो कांफ्रेंस की थी। पिछले वर्ष हमने मिल कर Petrapole ICP का उद्घाटन भी इसी प्रकार किया

था और मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी कनेक्टिविटी को मज़बूत करने वाले महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हमने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से किया।

उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है हमारी पीपुल-टू-पीपुल कनेक्टिविटी और आज international passenger terminus के उद्घाटन से कोलकाता-ढाका मैत्री एक्सप्रेस और आज शुरू हुई कोलकाता-खुलना बंधन एक्सप्रेस के यात्रियों को काफी सुविधा होगी। ■

आसियान के साथ और मजबूत हुए संबंध

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 12 से 14 नवंबर के बीच तीन-दिवसीय यात्रा पर फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहे। यह श्री मोदी की फिलीपींस की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, जहां प्रधानमंत्री ने आसियान-भारत और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलनों में भाग लिया। श्री मोदी की इस भागीदारी से सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दायरे में विशेष रूप से आसियान के सदस्य देशों के साथ और सामान्य रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को लगातार मजबूती देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता जाहिर होती है।

आसियान व्यवसाय और निवेश शिखर सम्मेलन, मनीला में 13 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और फिलीपींस की अनेक विषयों में समानता है :

- हम दोनों बहुलवादी समाज हैं और आकर्षक लोकतंत्र हैं।
- विश्व में हमारी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं।
- हमारे पास नवाचारी और उद्यमी युवा और महत्वाकांक्षी आबादी है।
- भारत की तरह ही फिलीपींस सेवा क्षेत्र का पावर हाउस है।

भारत की तरह ही फिलीपींस में भी सरकार परिवर्तन चाहती है, समावेशी विकास, संरचना विकास और भ्रष्टाचार से लड़ना चाहती है। हमारी अनेक शीर्ष आईटी कंपनियों ने यहां निवेश किया है। ये कंपनियां हजारों रोजगार सृजन कर रही हैं और पूरे विश्व में फिलीपींस के सेवा क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की एक्ट ईस्ट नीति इस क्षेत्र को सहयोग के केंद्र में रखती है। आसियान क्षेत्र के प्रत्येक देश के साथ हमारे असाधारण राजनीतिक और जन संबंध हैं। हम इसी स्तर पर अपने आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को लाना चाहते हैं।

श्री मोदी ने कहा कि अप्रत्याशित स्तर पर भारत को बदलने का काम किया जा रहा है। हम सहज, प्रभावी और पारदर्शी शासन संचालन सहित सुशासन सुनिश्चित करने के लिए रात-दिन काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने दूरसंचार स्पेक्ट्रम, कोयला खदानों तथा अन्य खनिजों और यहां तक की निजी रेडियो चैनलों सहित प्राकृतिक संसाधनों के लिए खुली नीलामी की व्यवस्था शुरू की है। इससे राजस्व में 75 बिलियन अमेरीकी डॉलर मिला है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम दायित्व बढ़ा रहे हैं तथा विवेकाधिकार और भ्रष्टाचार को कम कर रहे हैं। इसके लिए हम वित्तीय लेनदेन और कराधान में यूनिक आईडी सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और इसके परिणाम दिखने लगे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्च मूल्य के नोटों को बंद करने के साथ-साथ इन कदमों से हम अपनी अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक रूप दे रहे हैं। आयकर रिटर्न भरने वाले नए करदाताओं की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के साथ एक वर्ष में डिजिटल लेन-देन में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों तक पहुंचने के लिए किया है। ऑनलाइन नागरिक भागीदारी मंच से 2 मिलियन अति सक्रिय नागरिकों की ओर से सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में विचार और सुझाव तथा इनपुट मिले हैं।

श्री मोदी ने कहा कि हमने प्रगति नामक नया मंच प्रारंभ किया है, जो सक्रिय शासन संचालन और समयबद्ध कार्यक्रम क्रियान्वयन के लिए है। मैं इसके अंतर्गत पूरे देश के अधिकारियों के साथ वीडियों कांफ्रेंस के जरिये परियोजना क्रियान्वयन और लोक शिकायत समाधान की समीक्षा कर पाता हूं। न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन पर बल देते हुए तीन वर्षों में 1200 पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिवालियापन और दिवाला और आइपीआर तथा मध्यस्थता के लिए नए कानून और संस्थान बनाए गए हैं। 36 उद्योगों को पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता दायरे से बाहर निकाला गया है। अब कंपनी का निगमीकरण एक दिन की बात हो गई है। हमने औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया है तथा पर्यावरण और वन मंजूरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ की है। इन सभी कदमों से नया कारोबार शुरू करना सहज हो गया है और परिणाम स्पष्ट हैं।

श्री मोदी ने कहा कि भारत ने इस वर्ष विश्व बैंक कारोबारी सुगमता सूचकांक में 32 स्थानों की छंलाग लगाई है। किसी भी देश की यह सबसे बड़ी छलांग है और यह भारत के दीर्घकालिक सुधार मार्ग को मान्यता है।

और विश्व इस पर ध्यान दे रहा है :

- विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक स्पर्धी सूचकांक में हम पिछले 2 वर्षों में 32 स्थान आगे बढ़े हैं।

अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान और महावीर फिलीपीन फाउंडेशन का दौरा किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 13 नवंबर को फिलीपींस स्थित लॉस बनोस में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान (आईआरआरआई) का दौरा किया। आईआरआरआई एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान है जो चावल विज्ञान के जरिए गरीबी और भुखमरी में कमी करने, चावल उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं का स्वास्थ्य बेहतर करने तथा खुशहाली बढ़ाने और भावी पीढ़ियों के लिए चावल पैदावार हेतु अनुकूल माहौल बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री ने एक फोटो प्रदर्शनी भी देखी। इसमें बाढ़ रोधी चावल किस्मों, सूखा रोधी चावल किस्मों, लवणता रोधी चावल किस्मों और महिला कृषि सहकारी समितियों के साथ आईआरआरआई के कार्यों से जुड़ी फोटो प्रदर्शित की गई थीं।

प्रधानमंत्री ने डूब रोधी चावल किस्मों के रोपण के लिए एक नए भूखंड में प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी खोदी। उन्होंने 'श्री नरेन्द्र मोदी रिसिलिएंट राइस फील्ड लैबोरेटरी' के उद्घाटन अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण किया। उन्होंने आईआरआरआई जीन बैंक को चावल बीज की दो भारतीय किस्में सौंपीं।

प्रधानमंत्री ने मनीला स्थित महावीर फिलीपीन फाउंडेशन का भी दौरा किया। यह भारत और फिलीपींस के बीच दीर्घकालिक मानवीय सहयोग कार्यक्रम है। इसकी स्थापना मनीला के भारतीय मूल के मेयर डॉ. रमन बगटसिंग ने की थी। महावीर विकलांग सहायता समिति के सहयोग से इस फाउंडेशन ने जरूरतमंदों को आवश्यक पैर सुलभ कराने के लिए 'जयपुर फुट' की फिटमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- हम 2 वर्षों में डब्ल्यूआईपीओ के वैश्विक नवाचार सूचकांक में 32 स्थान आगे बढ़े हैं।
- हमने विश्व बैंक के लाजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2016 में 19 स्थानों की छलांग लगाई है।

उन्होंने कहा कि अब हमारी अर्थव्यवस्था के अधिकतर क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए खुले हैं। एफडीआई क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक स्वतः मंजूरी दायरे में है। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए अग्रणी रूप में उभरा है। हमें पिछले तीन वर्षों की तुलना में इस वर्ष 67 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुए हैं। अब हम वैश्विक रूप से एकीकृत अर्थव्यवस्था हैं। हाल के कुछ बड़े सुधारों से पहले यह उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष जुलाई में हमने पूरे देश में एकरूप वस्तु और सेवाकर प्रणाली लागू की है। पूरे भारत में अनेक राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय करों को समाप्त कर दिया गया है। हमारे देश की विशालता और विविधता और संघीय स्वभाव को देखते हुए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। साथ-साथ हम मानते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है।

उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं थी। इससे यह आबादी बचत के अवसरों तथा संस्थागत ऋण से वंचित हो जाती थी। जन धन योजना से कुछ महीनों के अंदर ही लाखों भारतीयों के जीवन में बदलाव आया है। एक वर्ष में 197

भारत फिलीपींस के बीच हुए चार समझौते

भारत और फिलीपींस ने रणनीतिक साझेदारी की ओर कदम बढ़ाते हुए रक्षा, कृषि एवं लघु उद्योग एवं राजनय के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए चार अहम समझौतों पर 13 नवंबर को हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति श्री रोड्रिगो गुतेत्रे के बीच द्विपक्षीय बैठक के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा कृषि, लघु, मध्यम एवं सूक्ष्म उद्यम तथा भारतीय नियंत्रण संबंध परिषद और फिलीपींस के समकक्ष संस्थान के बीच सहयोग के तीन करार पर भी दस्तखत किए गए।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात

फिलीपींस में चल रहे आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। 6 महीनों में दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और ये रोजाना नयी ऊंचाईयों को छू रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश एशिया और मानवता के हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने का मौका मिला है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप जहां भी गये हैं; अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां भी उन्हें भारत के बारे में बात करने का मौका मिला है; वहां पर उन्होंने भारत की तारीफ की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर दुनिया का भविष्य बदल सकते हैं।

यही नहीं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जापानी समकक्ष श्री शिंजो अबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री मैल्कम टर्नबुल के साथ अलग-अलग मुलाकात की। इस दौरान चतुर्भुज गठबंधन (भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका) की उभरती पृष्ठभूमि में भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई रणनीति बनाने पर फोकस किया गया। इससे पहले 12 नवंबर को भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने चतुर्भुज गठबंधन को आकार देने के लिए बैठक हुई। श्री मोदी ने ट्वीट किया कि मेरे दोस्त शिंजो अबे और मैंने भारत-जापान संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और हमारी अर्थव्यवस्थाओं व लोगों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।

आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने जिन राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की उनमें ब्रुनेई के सुल्तान श्री हसनल बी. ओलकिया, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री जैकिंद अर्दर्न और वियतनाम के प्रीमियर श्री गुयेन शुआन भी शामिल थे।

मिलियन बैंक खाते खोले गए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष अगस्त तक भारतीय बैंकों में ऐसे 290 मिलियन खाते खोले गए हैं। सहज नकद रहित लेनदेन के लिए लगभग 200 मिलियन रूपे कार्ड जारी किए गए। बैंकिंग सेवाओं तक गरीब लोगों की पहुंच सरकार में भ्रष्टाचार से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण रूप में सब्सिडी, गरीबों के खाते में प्रत्यक्ष रूप से जमा कर दी जाती है। इससे चोरी खत्म हो गई है और किसी तरह के विवेकाधिकार की संभावना नहीं रह गई है। केवल रसोई गैस के मामले में बैंक खातों के जरिये 146 मिलियन लोग प्रत्यक्ष नकद सब्सिडी प्राप्त कर रहे हैं। आज सरकार 59 अलग-अलग योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग कर रही है। वांछित लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 10 मिलियन अमेरीकी डॉलर की सब्सिडी अंतरित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि इस शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय उद्यमिता है। **हमने 'मेक इन इंडिया' नामक अभियान प्रारंभ किया है। उसके माध्यम से हम भारत को वैश्विक वैल्यू चेन में प्रमुख भागीदार के रूप में बदलने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम भारत को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग केंद्र बनाना चाहते हैं। साथ-साथ हम चाहते हैं कि हमारे युवा रोजगार सृजनकर्ता बनें, न कि महज रोजगार चाहने वाले बनें। इसके लिए हमने स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया अभियान लांच किया है।** छोटे उद्यमियों की उद्यमी ऊर्जा को मुक्त बनाने में एक प्रमुख बाधा है कि वित्त के लिए गारंटी की कमी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में पहली बार मुद्रा योजना के अंतर्गत गारंटी मुक्त ऋण 90 मिलियन से अधिक छोटे उद्यमियों को दिए गए हैं। यह अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमियों के योगदान को मान्यता देना है और ऐसे व्यक्ति को सशक्त बनाना है जिसके पास कामकाजी कारोबार का विचार है, लेकिन किसी तरह की गारंटी नहीं है।

उन्होंने कहा कि मैं फिलीपींस और आसियान क्षेत्र में उद्यमिता को दिए जा रहे महत्व को देख रहा हूं। इस शिखर सम्मेलन में उद्यमियों के लिए आसियान संरक्षण सराहनीय कदम है। वास्तव में निकट भविष्य में विश्व विकास का इंजन दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया होगा। हम इस क्षेत्र में भूमि, समुद्र और वायु संपर्क बनाना चाहते हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य देशों को जोड़ने के लिए म्यांमार और थाइलैंड के जरिये त्रिपक्षीय बनाने का काम जारी है।

श्री मोदी ने कहा कि हम भारत और आसियान के बीच समुद्री परिवहन पर समझौता शीघ्र संपन्न कराने के लिए काम कर रहे हैं और अपने निकटतम समुद्री पड़ोसियों के साथ तटीय जहाजरानी सेवाओं की संभावना तलाश रहे हैं। वायु संपर्क के क्षेत्र में आसियान देश भारत के चार मेट्रो शहरों और 18 अन्य स्थानों के लिए दैनिक सेवा प्रदान करते हैं। हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रानिक वीजा देने जैसे कदम उठाए हैं। ■

आर्थिक लोकतंत्र का आगाज

रामबहादुर राय

देश आर्थिक लोकतंत्र की अनूठी परंतु चिरप्रतीक्षित यात्रा पर निकल पड़ा है। इसकी शुरुआत आठ नवम्बर, 2016 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा से हुई। वह नोटबंदी का ऐलान था। उसका प्रभाव जहां देश में हुआ। इससे अर्थव्यवस्था में नगदी का चलन कम हुआ। काले धन पर लगाम लगी है। आर्थिक सुधार के लक्षण चौतरफा प्रकट हो रहे हैं।

मोदी से पहले हर प्रधानमंत्री ने काले धन पर चिंता जताई पर धीमी आवाज में। वैसे, काले धन से लड़ने की घोषणा तो सभी करते रहे हैं। समय-समय पर कुछ कदम भी उठाए गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या काला धन है। सबसे पहले 1948 में इसे पहचाना गया था, लेकिन इस समस्या का जिक्र राजनीतिक मंच पर पहली बार 1962 में हुआ और उसकी अनुगूंज पूरे देश ने सुनी। जब कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी ने भ्रष्टाचार और काले धन के प्रभाव में आए कांग्रेसियों पर सवाल खड़ा किया। पं. नेहरू उस आवाज को अनसुना नहीं कर सके। एक कमेटी बनाई। उसे संथानम कमेटी कहते हैं। तब से दर्जनों कमेटी और कमीशन बन चुके हैं। उनकी रिपोर्ट और सिफारिशें हर सरकार में धूल चाट रही थीं। उनमें ही एक एनएन वोहरा कमेटी की रिपोर्ट भी है, जो कभी उजागर नहीं हुई। उसने काले धन की तिकड़ी का राज खोला। उम्मीद थी कि केंद्र की सरकार उस रिपोर्ट को आधार बनाकर काले धन के गठजोड़ को तोड़ेगी। वह काम मोदी ने एक झटके में कर दिखाया। दूसरे क्यों नहीं कर सके?

आजादी के बाद से ही अर्थव्यवस्था में काले धन का प्रवेश हो गया था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कारोबारियों ने लाइसेंस प्रणाली का लाभ उठाकर काली कमाई की थी। 1948 में काले धन का अनुपात तीन फीसद आंका गया था, जो नेहरू के कार्यकाल में बढ़कर सात फीसद हो गया। वांचू कमेटी की रिपोर्ट यही बताती है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में नेहरू शासन से तीन गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई। उससे चिंतित जेपी ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई तो 29 अक्टूबर, 1977 को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उसमें केंद्र की मोरारजी देसाई सरकार से अपील की कि ऐसा कदम उठाएं, जिससे लोग अनुभव करें कि जनजीवन में सार्थक परिवर्तन होने जा रहा है। मोरारजी देसाई को काली ताकतों ने परास्त कर दिया अन्यथा वे अवश्य कदम उठाते। राजनीतिक नेतृत्व की बहानेबाजी से काले धन का अनुपात बढ़ता गया। इंदिरा गांधी के जमाने में जब उनसे जेपी सख्त कदम उठाने की बात करते थे, तब वे कहा करती थीं कि भ्रष्टाचार और काला धन तो विश्वव्यापी परिघटना है। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किसी का लिखा हुआ पढ़ा। वह आज एक मुहावरा बन गया है कि केंद्र से हर रुपये में से गरीबों को 15 पैसा ही मिल पाता है। यह बयान सच होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी से भागने का उपाय है। इसी तरह मनमोहन सिंह के कार्यकाल में काले धन का अनुपात बढ़कर 62 फीसद हो गया था। मोदी को 70 साल का कचरा साफ करना है। उन्होंने पाया कि नोटबंदी से एक साथ पांच लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। भारत

में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह के कदम का कोई उदाहरण नहीं मिलता। मोदी की घोषणा इसीलिए विशिष्ट हो जाती है।

नोटबंदी से एक ही साथ काले धन, जाली नोट, हवाला कारोबार, आतंकवादियों और माओवादियों के धन के स्त्रोत पर जहां मारक चोट पहुंची, वहीं डिजिटल भुगतान और साफ-सुथरी अर्थव्यवस्था के लिए बंद दरवाजे खुलने लगे। नोटबंदी से छह लाख करोड़ रुपये के काले धन को समाप्त किया जा सका है। इससे सचमुच पांच सकारात्मक परिणाम आए हैं। एक-बैंकों की कर्ज देने की क्षमता 18 लाख करोड़ रुपये की हो गई है। दो-डिजिटल लेन-देन की संख्या बढ़कर करीब 8 करोड़ हो गई है। तीन-3 लाख करोड़ नए बचत खाते खुले हैं। सोने का आयात बीस फीसद घटा है। म्यूच्यूअल फंड में 1.69 लाख करोड़ रुपये आए हैं, जो 17 सौ गुना पहले से ज्यादा हैं। चार-बैंक के कर्ज दरों में दो प्रतिशत की कमी आई है। यह रोजगार को बढ़ाने में सहायक होगा। पांच-वैध अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा है। नागरिकों में भावना पैदा हुई है कि काले धन वाले दंडित होंगे।

काले धन की अपनी एक प्रणाली है। उसे सिर्फ एक घोषणा से समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मोदी सरकार ने नई प्रक्रिया प्रारंभ की है। उससे अर्थव्यवस्था में अस्थायी अस्थिरता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि यह अल्पकालिक है। दूसरी तरफ काले धन से निपटने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है, उसके तहत ही ब्लैक मनी एंड इंपोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट जैसे कानून अपना काम कर रहे हैं। इससे 64,275 व्यक्तियों ने अपने काले धन की जानकारी दी। इससे भारत सरकार को 2,476 करोड़ टैक्स मिला। इस तरह के चार-पांच कदम सरकार ने उठाए हैं। कुछ कानूनों में संशोधन कर इस प्रक्रिया को तेज किया गया है, जिससे बेनामी संपत्ति से भी पैदा काले धन को रोका जा सके। 30 सितम्बर, 2017 तक 1626 करोड़ रुपये मूल्य के 475 मामले पकड़े गए। करीब 18 लाख संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनमें करीब 4 लाख करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ है।

राजनीतिक नेतृत्व और राज्य तंत्र की मदद के बिना काले धन की अर्थव्यवस्था काम नहीं कर सकती। विपक्ष भी यह जानता है। इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुद से पूछना चाहिए कि काले धन का कंगूरा किसने बढ़ाया? इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने कहा है कि काले धन की अर्थव्यवस्था का साथ नहीं देगा। यह भी बता दिया है कि काले धन में राज्य तंत्र की हिस्सेदारी को भी चलने नहीं देंगे। सवाल है कि विपक्ष इससे क्यों बौखला गया है। एक नागरिक काले धन के खिलाफ मोदी की लड़ाई को अपने हित और देश के हित में समझता है। विपक्ष भी ऐसा सोच सकता है, अगर वह अपने मन को बदले और रचनात्मक राजनीति की राह ले। तभी आर्थिक लोकतंत्र की यात्रा अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच सकेगी। जो बाधा बनेंगे, वे इतिहास के अपराधी माने जाएंगे। ■

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं

(राष्ट्रीय सहारा से साभार)

प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार पर जोर दिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 नवंबर को अति सक्रिय गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए मल्टी मॉडल मंच सूचना और प्रौद्योगिकी आधारित-प्रगति प्लेटफार्म के माध्यम से अपने 23वें संवाद की अध्यक्षता की। पिछली 22 प्रगति की बैठकों में 9.31 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली 200 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इसमें 17 क्षेत्रों में जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई है।

इस 23वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने उपभोक्ताओं से संबंधित शिकायतों का संचालन और समाधान की दिशा में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री को उपभोक्ता शिकायतों के तीव्र और प्रभावी निपटान को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। बड़ी संख्या में शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रशासनिक प्रबंधन में सुधार के लिए जरूरत पर जोर दिया, जिससे कि उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, नगालैंड, असम, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सहित रेलवे, सड़क और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों की 9 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं की संचयी मूल्य 30 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक है।

प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पी एम के के के वाई) के कार्यान्वयन में प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशनों (डी एम एफ) द्वारा उपार्जित निधियों को अच्छी तरह और वर्तमान में इन जिलों द्वारा सामना की जा रही मुख्य विकासात्मक मुद्दों या कमियों को दूर करने के लिए समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे एक सोची-समझी रणनीति से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अर्थात् 2022 तक सर्वाधिक संभव मूर्त परिणामों को प्राप्त किया जा सके। ■

बनेगी विकासमाला

देश और दुनिया के अर्थ विशेषज्ञों का मानना है कि ''भारतमाला परियोजना' भारतीय अर्थव्यवस्था की नई जीवन रेखा बनने जा रही है।

| जयंतीलाल भंडारी |

हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाईवे) के विकास से संबंधित महत्त्वाकांक्षी ''भारतमाला प्रोजेक्ट' के तहत 83 हजार किलोमीटर की राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण को मंजूरी दी है। इन राजमार्ग का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा होगा और इन पर 6.92 लाख करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित है। "भारतमाला परियोजना" के लिए 70 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार खर्च करेगी और 30 फीसद हिस्सा निजी भागीदारी से आएगा। "भारतमाला परियोजना" से बड़े पैमाने पर रोजगार के नये अवसर निर्मित होंगे। अनुमान है कि इस योजना से अगले पांच वर्षों में लोगों को 14.2 करोड़ कार्य दिवस का रोजगार मिल सकेगा। गौरतलब है कि ''भारतमाला परियोजना' देश में ''स्वर्णिम चतुर्भुज योजना' के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राजमार्ग विकास परियोजना है।

देश के जिन राज्यों की सीमाएं इस परियोजना की परिधि में आएगी, उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, मणिपुर और मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा शामिल है। "भारतमाला परियोजना" के तहत कुल 44 आर्थिक गलियारों की पहचान की गई है। 26,200 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारों को चिह्नित किया गया है। इसमें से 9000 किलोमीटर आर्थिक गलियारे का विकास पहले चरण में होगा। गलियारे के तहत बेंगलुरू-मेंगलुरू, मुंबई-कोचीन-कन्याकुमारी, हैदराबाद-पणजी, संबलपुर-रांची के मार्ग शामिल हैं।

निश्चित रूप से अच्छी सड़कें किसी भी राष्ट्र की जीवनरेखा मानी जाती हैं। जहां आर्थिक विकास के लिए यह महत्त्वपूर्ण है, वहीं सामाजिक विकास का भी यह अहम हिस्सा है। देश में यात्रियों की कुल संख्या में से 80 प्रतिशत से ज्यादा सड़क परिवहन से यात्रा करते हैं।

निश्चित रूप से अच्छी सड़कें किसी भी राष्ट्र की जीवनरेखा मानी जाती हैं। जहां आर्थिक विकास के लिए यह महत्त्वपूर्ण है, वहीं सामाजिक विकास का भी यह अहम हिस्सा है। देश में यात्रियों की कुल संख्या में से 80 प्रतिशत से ज्यादा सड़क परिवहन से यात्रा करते हैं। देश के विकास के लिए उचित सड़क नेटवर्क की आवश्यकता को बहुत पहले ही समझ लिया गया था। 1943 में बनाई गई नागपुर योजना के नाम से विख्यात, पहली सड़क विकास योजना में पहली बार देश में सड़कों की जरूरत को दीर्घकालिक आधार पर देखा गया और पहली बार ही सड़क प्रणाली को कार्यात्मक अनुक्रम में वर्गीकृत किया गया, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राज्य राजमार्ग (एसएच), प्रमुख जिला सड़कें (एमडीआर) अन्य जिला सड़कें (अडीआर) और ग्राम सड़कें (वीआर) शामिल थीं। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है।

यद्यपि देश में लगभग 46.90 लाख किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विशाल नेटवर्क है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 82,803 किलोमीटर ही है, जो सड़कों के कुल नेटवर्क के दो प्रतिशत से कम है। राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए देश में ''राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम' की 1998 में शुरुआत की गई थी। इसके तहत ''स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना' के नेटवर्क से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ा गया है। यह भारत में सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया में पांचवां क्रम रखती है। हालांकि इसे पूरा होने में काफी वक्त लग गया। ऐसे में यह शुभ संकेत है कि केंद्र सरकार ने "भारतमाला योजना" को "स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना" में

हुए विलंब के परिदृश्य से बचाते हुए समय पर पूरा करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया है।

सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना पर निजी क्षेत्र की ओर से जबरदस्त समर्थन मिलेगा। इस परियोजना के तहत सभी परियोजनाओं की तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक मंजूरी एनएचएआई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाली परियोजना मंजूरी और तकनीकी जांच की अधिकार प्राप्त समिति करेगी। परियोजनाओं की जांच के लिए दिशा-निर्देश पहले ही तैयार कर लिये गए हैं। निसंदेह "भारतमाला परियोजना" से मौजूदा राजमार्ग बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी, जिससे यात्रियों व माल की आवाजाही सुगम हो जाएगी।

"भारतमाला परियोजना" से आर्थिक गलियारों में यातायात तेज होगा। इससे ग्रामीण इलाकों में भी सड़कों के विकास को गति मिलेगी। राजमार्ग के तेजी से विकास से निजी क्षेत्र के लिए अवसर बढ़ेंगे। इस योजना को लागू किए जाने से भारत में विनिर्माण क्षेत्र में बहुप्रतीक्षित लागत प्रतिस्पर्धात्मकता आएगी, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके साथ ही प्रमुख शहरों के बीच तय किए जाने वाले समय में भी काफी कमी आएगी। इस परियोजना से छोटे शहरों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। ग्रामीण इलाकों से उपज की बेहतर परिवहन व्यवस्था के कारण किसानों के लिए आर्थिक सम्पन्नता और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चूंकि भारत दुनिया में फल व सब्जी का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन अच्छी सड़कों व भंडारण की कमी के कारण करीब 35 फीसद फल व सब्जी खराब हो जाती है। ऐसे में भारतमाला परियोजना से फल व सब्जी उत्पादों का अच्छा इस्तेमाल होगा और देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस परियोजना से पिछड़े और आदिवासी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इस परियोजना से सीमा वाले इलाकों, तटीय इलाकों और पड़ोसी देशों के लिए कारोबारी मार्ग संबंधी लाभ भी बढ़ जाएंगे।

हम आशा करें कि केंद्र सरकार शुरुआत से ही भारतमाला परियोजना के क्रियान्वयन के हर कदम पर उपयुक्त निगरानी रखेगी। साथ ही इस परियोजना के लिए समय प्रबंधन और लागत प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन किया जाएगा। यह भी उपयुक्त होगा कि सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत समय से पहले ठेके पूरा करने वाले ठेकेदारों को कुल परियोजना लागत का 10 फीसद तक बोनस दिया जाना सुनिश्चित किए जाने से सड़क निर्माण को रफ्तार मिलेगी। ऐसा किए जाने पर निश्चित रूप से भारतमाला परियोजना देश के ढांचागत विकास में मील का पत्थर साबित होगी। साथ ही यह परियोजना देश की विकास रेखा सिद्ध होगी और इससे अर्थव्यवस्था तेजी से गतिशील होगी। ■

लेखक आर्थिक विश्लेषक हैं

(राष्ट्रीय सहारा से साभार)

सरकार ग्रामीण आवास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक साल पहले 20 नवंबर, 2016 को आगरा से 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' का शुभारंभ किया था। लाभार्थियों के पंजीकरण, भू-टैगिंग और खाता सत्यापन के बाद एक करोड़ नये मकानों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 51 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 मार्च, 2018 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था।

इस योजना के शुभारंभ के बाद लाभार्थियों के पंजीकरण, भू-टैगिंग, खाता सत्यापन, इत्यादि की प्रक्रिया पूरी करने में कुछ महीने लग गये। 55.85 लाख मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है और इस दिशा में कार्य प्रगति पर है। इनमें से लगभग 30 लाख मकानों का निर्माण कार्य छत तक पूरा हो चुका है, जबकि 15 लाख मकानों का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। 20 नवम्बर, 2017 तक 9.03 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 10 लाख मकानों का निर्माण कार्य 30 नवम्बर 2017 तक, 15 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 दिसम्बर 2017 तक, 25 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 जनवरी 2018 तक, 35 लाख मकानों का निर्माण कार्य 28 फरवरी 2018 तक और 51 लाख मकानों का निर्माण कार्य 31 मार्च 2018 तक पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

नये डिजाइनों, स्थानीय भवन निर्माण सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण, परिसंपत्तियों की भू-टैगिंग और आईटी-डीबीटी प्लेटफॉर्म के जरिये लाभार्थियों के खातों में भुगतान सीधे भेजने से पारदर्शितापूर्ण, बाधामुक्त और गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ है। सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश संबंधित लाभार्थियों की सहूलियत के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनके मकानों का निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके। सामाजिक-आर्थिक जनगणना (एसईसीसी 2011) के उपयोग, ग्राम सभा द्वारा सत्यापन और भू-टैगिंग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से इसमें न्यूनतम समावेशी त्रुटियां सुनिश्चित हुई हैं। इस गरीब हितैषी कार्यक्रम के तहत केवल वही लोग लाभार्थी हैं, जो बेघर हैं अथवा कच्ची छत एवं एक कमरे वाले कच्चे घरों में या कच्ची छत एवं दो कमरों वाले कच्चे घरों में रहते हैं। गरीबों को सशक्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है। ■

वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को फिक्सड कहना कांग्रेस की हताशा

| डॉ. नीलम महेंद्र |

जब नोटबंदी और जीएसटी को देश की घटती जीडीपी और सुस्त होती अर्थव्यवस्था का कारण बताते हुए सरकार लम्बे अरसे से लगातार अपने विरोधियों के निशाने पर हो और 8 नवंबर को विपक्ष द्वारा काला दिवस मनाने की घोषणा की गई हो, ऐसे समय में कारोबारी सुगमता पर विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट सरकार के लिए एक ठंडी हवा का झोंका बनकर आई है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस इस रिपोर्ट को ही फिक्सड कहते हुए अपनी हताशा जाहिर कर रही है वो निश्चित ही अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी इस प्रकार की नकारात्मक रणनीति के परिणामस्वरूप आज न सिर्फ कांग्रेस खुद ही अपने पतन का कारण बन रही है, बल्कि देशवासियों को पार्टी के रूप में कोई विकल्प और देश के लोकतंत्र को एक मजबूत विपक्ष भी नहीं दे पा रही है। सरकार के विरोधियों को उनका जवाब शायद वर्ल्ड बैंक की "ईज आफ डूइंग बिजनेस" रैंकिंग की ताजा रिपोर्ट में मिल गया होगा, जिसमें इस बार भारत ने अभूतपूर्व 30 अंकों की उछाल दर्ज की है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों का परिणाम ही है कि 190 देशों की इस सूची में भारत 2014 में 142 वें पायदान पर था, 2017 में सुधार करते हुए 130 वें स्थान पर आया और अब पहली बार वह इस सूची में 100 वें रैंक पर है।

रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि भारत को इस साल सबसे अधिक सुधार करने वाले दुनिया के टॉप टेन देशों में शामिल किया गया है और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के मामले में यह शीर्ष पर है।

अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो महज 0.40 अंकों के सुधार के साथ चीन 78 वें पायदान पर है, पाकिस्तान 147 और बांग्लादेश 177 पर। सरकार का लक्ष्य 2019 में 90 और 2020 तक 30 वें पायदान पर आना है। प्रधानमंत्री का कहना है कि "सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण के मंत्र की मार्गदर्शिका के अनुसार हम अपनी रैंकिंग में और सुधार के लिए और अधिक आर्थिक वृद्धि को पाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" रिपोर्ट की सबसे खास बात यह है कि भारत को इस साल सबसे अधिक सुधार करने वाले दुनिया के टॉप टेन देशों में शामिल किया गया है और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के मामले में यह शीर्ष पर है। भारत के लिए निःसंदेह यह गर्व की बात है कि इस प्रतिष्ठित सूची में वह दक्षिण एशिया और ब्रिक्स समूह का एकमात्र देश है।

2003 में जब यह रिपोर्ट जारी की गई थी, तब इसमें 5 मुद्दों के आधार पर 133 देशों की अर्थव्यवस्था को शामिल किया था, लेकिन इस साल 11 बिन्दुओं के आधार पर 190 देशों की अर्थव्यवस्था में यह रैंकिंग की गई है। चूकि विश्व बैंक की यह रिपोर्ट हर साल 1 जून तक के प्रदर्शन पर आधारित होती हैं, इसलिए इस साल एक जुलाई से लागू किए गए जीएसटी और उसके प्रभाव को इसमें शामिल नहीं किया गया है। वर्ल्ड बैंक के साउथ एशिया के उपाध्यक्ष डिक्सन का कहना है कि यह रिपोर्ट संकेत देती है कि भारत के दरवाजे कारोबार के लिए खुले हैं और अब यह विश्व स्तर पर व्यापार करने के लिए पसंदीदा स्थान के रूप में कड़ी टक्कर दे रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी ने गुजरात को व्यापार की दृष्टि से "गेटवे आफ इंडिया" बना दिया था। देश के लगभग सभी बड़े औद्योगिक घराने अन्य राज्यों की अपेक्षा गुजरात को उसकी आर्थिक नीतियों के कारण निवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य मानते थे। विश्व बैंक की यह ताजा रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि अपनी नई आर्थिक नीतियों के सहारे भारत आज व्यापार और निवेश की दृष्टि से दुनिया की नजरों में पहले के मुकाबले कहीं अधिक आकर्षक और उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आने वाले समय में शायद भारत विदेशी निवेश की दृष्टि से "गेटवे आफ द वर्ल्ड" बन जाए।

दिल्ली और मुंबई के कॉर्पोरेट जगत से मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गयी इस रिपोर्ट के अनुसार जहां पहले नया व्यवसाय शुरू करने के लिए व्यक्ति को बैंक से लोन लेने से लेकर विभिन्न कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए महीनों पसीना बहाने के साथ साथ अपनी मेहनत की कमाई भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ानी पड़ती थी। आज अधिकतर प्रक्रिया आनलाईन करके लालफीताशाही पर भी लगाम लगाने की काफी हद तक सफल कोशिश की गई है। कर्ज लेना आसान बनाकर न सिर्फ देश में 'स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया' के द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा दिया गया, बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित किया गया।

देश में अब तक छोटे निवेशकों के हितों को अनदेखा किया जाता था, लेकिन अब सेबी द्वारा छोटे निवेश में भी सुरक्षा देने के लिहाज से कई कदम उठाए गए जिनके आधार पर भारत ने इस क्षेत्र में नौ पायदान ऊपर आते हुए चौथी रैंकिंग हासिल की। टैक्स सुधारों के परिणामस्वरूप पहले की 172 रैंकिंग के मुकाबले इस बार 53 अंकों की उछाल के साथ भारत 119 वें स्थान पर है। हालांकि आयात निर्यात जैसे क्षेत्र में भारत सरकार को अभी और काम करना है लेकिन दस में से आठ क्षेत्रों में सुधार के साथ यह कहा जा सकता है कि विरोध करने वाले जो भी कहें, देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है। ■

लेखिका स्तंभकार हैं

भारतीय रेल को 'बिजली ट्रैक्शन ऊर्जा बिल' से 5636 करोड़ रुपये की बचत

बिजली ट्रैक्शन ऊर्जा बिल घटाने की प्रमुख रणनीति अपनाते हुए भारतीय रेल को खुली पहुंच व्यवस्था (ओपन एक्सेस) के अंतर्गत सामान्य कारोबार (बीएयू) मोड में सीधे बिजली खरीदने से अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2017 तक 5636 करोड़ रुपये की संचयी बचत हुई। यह संचयी आंकड़ा चालू वित्त वर्ष के अंत तक यानी मार्च 2018 तक बढ़कर 6927 करोड़ रुपये हो सकता है। यह निर्धारित लक्ष्य से हजार करोड़ रुपये अधिक है।

इन मदों में अनुमानित बचत से संकेत मिलता है कि दस वर्ष (2015-2025) में 41,000 करोड़ रुपये की संचयी बचत बिजली ट्रैक्शन बिल में हो सकती है। इसे भारतीय रेल का मिशन- 41,000 नाम दिया गया है। विशाल ऊर्जा बिल में कारगर बचत के उद्देश्य से भारतीय रेल ने खुली पहुंच (ओपन एक्सेस) व्यवस्था के अंतर्गत बिजली खरीद प्रबंधन में नवाचारी कदम उठाये।

यह कहा जा सकता है कि बिजली अधिनियम, 2003 ने भारतीय रेल को बिजली उत्पादन, संप्रेषण तथा भारत में बिजली आने के समय से ऊर्जा वितरण में भागीदारी के कारण मानद लाइसेंसी का दर्जा दिया। इसी के अनुसार भारतीय रेल ने बिजली अधिनियम के प्रावधान पर संचालन का कार्य शुरू किया, लेकिन विभिन्न कारणों से कुछ समय तक यह काम आगे नहीं बढ़ सका।

बाद में रेल मंत्री ने नई गति के साथ इस कार्य को लिया और एक रणनीति बनाई गई। इसके अनुरूप वर्तमान संप्रेषण नेटवर्क के आधार पर मानद लाइसेंसी के रूप में खुली पहुंच व्यवस्था में सहायता देने के लिए भारतीय रेल ने केन्द्रीय बिजली नियामक आयोग (सीआरसी) से सभी राज्यों की सम्प्रेषण कंपनियों (एसटीयू) तथा राज्यों के लोड डिस्पैच केन्द्रों (एसएलडीसी) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए सम्पर्क किया। अन्ततः 26 नवम्बर, 2015 को मानद लाइसेंसी के रूप में बिजली ऊर्जा लेने का भारतीय रेल का विजन उस समय पूरा हुआ, जब भारतीय रेल ने महाराष्ट्र में गैस आधारित बिजली संयंत्र रत्नागिरी गैस पॉवर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) से 200 मेगावाट बिजली लेना प्रारंभ किया।

भारतीय रेल ने पहली बार राज्य वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए वितरण लाइसेंसी के रूप में खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत बिजली ली। भारतीय रेल ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में खपत के लिए और झारखंड में विद्युत ट्रैक्शन बिजली आवश्यकता के लिए आरजीपीपीएल से 500 मेगावाट लेने का समझौता किया। 22 जनवरी, 2016 तक इन चारों राज्यों में बिजली प्रवाह का काम पूरा हुआ। भारतीय रेल ने दादरी से कानपुर तक अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए खुली निविदा के माध्यम से 50 मेगावाट बिजली ली और इसमें बिजली प्रवाह कार्य 01 दिसम्बर, 2015 से शुरू हुआ। राजस्थान में 01 जनवरी, 2017 से, दामोदर घाटी निगम में अगस्त, 2017 से और हरियाणा तथा कर्नाटक में अक्टूबर, 2017 से बिजली प्रवाह शुरू है।

रेल मंत्रालय के निरंतर प्रयास तथा प्रधानमंत्री कार्यालय सहित भारत सरकार के समर्थन से वर्तमान में विद्युत ट्रैक्शन के लिए बिजली सात राज्यों (महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा तथा कर्नाटक) तथा दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत ली जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और तेलंगाना खुली पहुंच व्यवस्था के माध्यम से बिजली प्रवाह के लिए भारतीय रेल को अनुमति देने पर सहमत हो गये है। यह कार्य अगले वर्ष तक शुरू हो सकता है। खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत बिजली खरीदने के लिए भारतीय रेल शेष राज्यों से बातचीत कर रहा है।

अभी भारतीय रेल की 2,000 मेगावाट की कुल आवश्यकता में से विद्युत ट्रैक्शन बिजली 1,000 मेगावाट से अधिक खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त की जा रही है। इससे इन राज्यों में बिजली की औसत लागत में कमी आई है। इन राज्यों में खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत पहले के मूल्य 7 रूपये प्रति यूनिट की तुलना में मूल्य 5 रुपये प्रति यूनिट है।

वितरण लाइसेंसी के रूप में भारतीय रेल द्वारा बिजली खरीदने से होने वाले तात्कालिक लाभों तथा भारतीय रेल के वित्तीय कार्य प्रदर्शन में इसके प्रभाव को भारतीय रेल के मिशन 41,000 दस्तावेज में वर्णित किया गया है। इन मदों में अनुमानित बचत से संकेत मिलता है कि 10 वर्षों (2015-2025) में इन कदमों से बिजली ट्रैक्शन बिल में 41,000 करोड़ रुपये की संचयी बचत होगी। इसे भारतीय रेल का मिशन-41,000 नाम दिया गया है।

बचत राशि का इस्तेमाल मिशन बिजलीकरण के हिस्से के रूप में शेष रेल नेटवर्कों के बिजलीकरण में किया जाएगा। इससे डीजल बिल में कमी आएगी और भारतीय रेल नेटवर्क के 100 प्रतिशत बिजलीकरण से अगले कुछ वर्षों में प्रति वर्ष 10,500 करोड़ रुपये की बचत होगी। ■

भारत की प्रथम 'एयर डिस्पेंसरी' पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थापित की जाएगी

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही भारत की प्रथम 'एयर डिस्पेंसरी' स्थापित की जाएगी, जो एक हेलिकॉप्टर में अवस्थित होगी। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) मंत्रालय ने इस पहल के लिए आरंभिक वित्त पोषण के एक हिस्से के रूप में 25 करोड़ रुपये का योगदान पहले ही कर दिया है। 12 नवंबर को इस आशय की जानकारी देते हुए केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पीएमओ, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस तरह के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर आधारित डिस्पेंसरी/ओपीडी सेवा सुलभ कराने की संभावनाएं तलाश रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यह सेवा उपलब्ध कराई जाएगी, जहां कोई भी डॉक्टर या चिकित्सा सुविधा सुलभ नहीं होती है और जरूरतमंद मरीजों को किसी भी तरह की चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और यह अब केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय में अनुमोदन के अंतिम चरण में है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने विमानन क्षेत्र और हेलिकॉप्टर सेवा/पवन हंस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद ये बातें कही।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस प्रस्ताव को गंभीरता के साथ आगे बढ़ा रहा है, ताकि वर्ष 2018 के आरंभ में यह केन्द्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र की आम जनता को एक अनुपम उपहार के रूप में प्राप्त हो सके। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी कि आज भी भारत की लगभग एक तिहाई आबादी को अस्पतालों में समुचित ढंग से बिस्तर उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके चलते दूरदराज के इलाकों में रहने वाले निर्धन मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सेवा सुलभ नहीं हो पाती है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पहल पर पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए जा रहे इस प्रयोग को अन्य पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी अपनाया जा सकता है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आरंभ में इस योजना के तहत हेलिकॉप्टर को दो स्थलों यथा मणिपुर के इम्फाल और शिलांग के मेघालय में अवस्थित किया जाएगा। इन दोनों ही शहरों में प्रमुख स्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थान हैं, जहां के विशेषज्ञ डॉक्टर आवश्यक उपकरणों एवं सहायक कर्मचारियों के साथ हेलिकॉप्टर के जरिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी आठों राज्यों के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर डिस्पेंसरी/ओपीडी सेवा मुहैया करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वापसी के दौरान उसी हेलिकॉप्टर से जरूरतमंद मरीज को शहर में लाकर संबंधित अस्पताल में भर्ती भी कराया जा सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अन्य नई हेलिकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आरंभ में इम्फाल, गुवाहाटी और डिब्रुगढ़ के आसपास अवस्थित क्षेत्र में छह मार्गों पर दोहरे इंजन वाले तीन हेलिकॉप्टरों का परिचालन सुनिश्चित किया जाएगा। ■

मंत्रिमंडल ने आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग के लिए भारत-रूस करार पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आतंकवाद के सभी रूपों और संगठित अपराध से निपटने के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है। इस करार पर गृहमंत्री के नेतृत्व में दिनांक 27 से 29 नवंबर, 2017 को रूस में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की आगामी यात्रा के दौरान हस्ताक्षर होना प्रस्तावित है।

गौरतलब है कि भारत और रूस का आपसी हितों के मामलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर निकट सहयोग का सुदीर्घ इतिहास है। विश्व भर में बढ़ते आतंकवाद और संगठित अपराध को ध्यान में रखते हुए सभी देशों के लिए आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करना अनिवार्य है। प्रस्तावित करार, जो अक्तूबर, 1993 के करार का स्थान लेगा, वह सुरक्षा के क्षेत्र में उपार्जित किए गए लाभों को एकत्र करने की दिशा में एक कदम है और यह नए एवं उभरते हुए जोखिमों और खतरों से संयुक्त रूप से निपटने का प्रस्ताव रखता है। इस करार के माध्यम से सूचना, विशेषज्ञता, बेहतर प्रथाओं के आदान-प्रदान और साझाकरण से भारत और रूस के बीच आपसी संबंधों को मजबूती मिलेगी। ■

प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए एक करोड़ आवास की कमी पूरी होगी

2011 में कराए गए एक तकनीकी अध्ययन में शहरी इलाकों में 18.76 मिलियन मकानों की कमी का आंकलन था, जिसमें 96 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस खंड और एलआईजी हाउसिंग में थी। इसके बाद किए गए आकलनों में इस आंकड़े में संशोधन हुआ और इसका अंतिम विश्लेषण किया जा रहा है।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुसार मकानों की यह कमी 10 मिलियन इकाइयों के आस-पास अथवा इससे अधिक हो सकती है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के जरिए दूर किया जाएगा। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने कहा कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), कम आय वाले समूह (एलआईजी) और मध्यम आय वाले समूह (एमआईजी) के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

श्री पुरी ने कहा कि हमने निजी भागीदारी के जरिए आवास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पीपीपी मॉडल जारी किए हैं। इस योजना की विशेषता है कि सरकार भूमि उपलब्ध कराएगी और प्रत्येक एलॉटी को सब्सिडी प्रदान करेगी और शेष धनराशि बैंकों से आसान शर्तों पर लेने में सहायता करेगी। आवास महिला के नाम पर अथवा परिवार के पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से होगा। इससे महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने में मदद मिलेगी। इसमें एक रसोई और शौचालय होगा तथा बालिका की सुरक्षा की व्यवस्था होगी।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अनुसार मकानों की यह कमी 10 मिलियन इकाइयों के आस-पास अथवा इससे अधिक हो सकती है, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के जरिए दूर किया जाएगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), कम आय वाले समूह (एलआईजी) और मध्यम आय वाले समूह (एमआईजी) के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराना है।

आवासीय क्षेत्र के महत्व पर जोर देते हुए श्री पुरी ने कहा कि आवास और देश में बुनियादी ढांचे की मांग को पूरा करने में यह उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है और कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें देश में 6.86 प्रतिशत कामगारों को रोजगार मिला हुआ है।

रियल एस्टेट कानून एक पथ प्रदर्शक कानून

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने कहा कि रियल एस्टेट कानून एक पथ प्रदर्शक कानून है, जिससे आने वाले समय में कायापलट होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिसमें रियल एस्टेट क्षेत्र का उचित तरीके से संचालन और खरीददार को मजबूत बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है। 'मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि भारत में रियल एस्टेट का इतिहास दो खंडों में देखा जाएगा, रेरा से पूर्व और रेरा के बाद। रेरा से पूर्व के चरण का वर्णन अनेक लोगों के घर का सपना और महत्त्वाकांक्षा के रूप में किया जा सकता है, जिस सपने को कुछ लोगों ने थोड़े से समय में चकनाचूर कर दिया। हम अभी उस चरण से नहीं निकले हैं।' श्री पुरी 15 नवंबर को 'नीति, सुधार और नियंत्रणः भारतीय रियल एस्टेट की रीढ़' विषय पर आरआईसीएस रियल एस्टेट सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

सम्मेलन में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए श्री पुरी ने कहा कि धनराशि का अभाव मकान लेने में एक समस्या है। आवासीय क्षेत्र में बहुत कम पारदर्शिता है। झूठे वादे, अपूर्ण आवासीय परियोजनाएं उन अभागे नागरिकों की अनकही विपत्तियों को दर्शाती है, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी मकान खरीदने में लगा दी है। हम अभी भी उन थोड़े से लोगों के सफाये की प्रक्रिया के आखिरी चरण में है, जिनकी चूक के कारण अनेक ऐसे डेवलपरों की छवि धूमिल हुई है जो अपना क्रय-विक्रय सही तरीके से कर रहे हैं। ■

भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने वाला देश

केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत परंपरागत रूप से दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कृषि करने वाला देश है। यहां तक कि मौजूदा भारत के बहुत बड़े भू–भाग में परंपरागत ज्ञान के आधार पर जैविक खेती की जाती है। श्री सिंह ने यह बात 9 नवंबर को इंडिया एक्सपो सेंटर, ग्रेटर नोएडा में जैविक कृषि विश्व कुम्भ 2017 का उद्घाटन करते हुए कही।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में वर्तमान में 22.5 लाख हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती हो रही है जिसमे परंपरागत कृषि विकास योजना से 3,60,400 किसान को लाभ पहुंचा है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रों में जैविक कृषि के अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य है। अब तक 45863 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक योग्य क्षेत्र में परिवर्तित किया जा चुका है और 2406 फार्मर इटेंरेस्ट ग्रुप (एफआईजी) का गठन कर लिया गया है, 2500 एफआईजी लक्ष्य के मुकाबले 44064 किसानों को योजना से जोड़ा जा चुका है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ हुई और 28750 एकड़ मे 28750 किसान को लाभ पहुंचा है। किसानों के जैविक उत्पादों के विपणन के लिए राज्य सरकार 5 लाख रुपये प्रति जनपद को देकर बिक्री केंद्र (Outlet) खुलवा रही है।

श्री सिंह ने कहा कि दुनिया के कुछ वैज्ञानिक इसे 'डिफाल्ट ऑर्गेनिक' कहते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जो किसान परंपरागत रूप से जैविक खेती कर रहे हैं, यह उनकी मजबूरी नहीं, उनकी पसंद है। बेहद गहरी समझ के साथ वो इस रास्ते पर सदियों से चल रहे हैं। आज, वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते तो यह उनकी अज्ञानता नहीं है, बल्कि उन्होंने बहुत सोच-समझकर ऐसा न करने का फैसला किया है। इसलिए उनकी इस खेती की विधि को 'बाई डिफाल्ट' नहीं कहा जा सकता।

श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारत सरकार इस बात को स्वीकार करती है कि पिछले कुछ दशकों में खेतों में रासायनिक खाद के अंधाधुंध उपयोग ने यह सवाल पैदा कर दिया है कि इस तरह हम कितने दिन खेती कर सकेंगे? रासायनिक खाद युक्त खेती से पर्यावरण के साथ सामाजिक-आर्थिक और उत्पादन से जुड़े मुद्दे भी हैं जो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।

श्री सिंह ने कहा कि अब देश में खाद्य आपूर्ति की कोई समस्या नहीं है, लेकिन देश की बढ़ती जनसंख्या को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण चुनौती का कार्य अभी शेष है। हमारी निर्भरता रासायनिक खेती पर हो गयी है जिसमे हम रासायनिक उर्वरक, कीट-रोग नाशी एवं अन्य रासायन का प्रयोग करके उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन अनियंत्रित उपयोग से असुरक्षित खाद्यान उत्पन्न करने की समस्या पनप गयी है ।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यदि हम इन रासायनिक आदानों के अंधाधुंध प्रयोग द्वारा पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभावों का विश्लेषण करे तो पता चलेगा कि इन सारे रासायनिक आदानो का बड़ा भाग मिट्टी,भू-जल,हवा और पौधों में समाविष्ट हो जाता है। यह छिड़काव के समय हवा के साथ दूर तक अन्य पौधों को प्रदूषित कर देते हैं। भूमि में प्रवेश करने वाले ये रसायन भू-जल में मिलकर, पानी के अन्य स्त्रोतों को भी प्रदूषित कर देता है। श्री सिंह ने कहा कि रसायनों के दुष्प्रभाव से विश्व में जलवायु परिवर्तन और प्रकृति के पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया है और मानवों पर भी गंभीर दुष्प्रभाव देखे गये हैं। धरती मां के स्वास्थ्य, सतत उत्पादन, आमजन को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्यान के लिए जैविक कृषि आज राष्ट्रीय एवं वैश्विक आवश्यकता है। ■

पत्र-पत्रिकाओं से...

उजली तस्वीर पर मुहर

भारत तेजी से खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, इस आम धारणा पर अब अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 'मूडीज ने भी मुहर लगा दी है। कुछ दिन पहले विश्व बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत ने 30 पायदान की ऊंची छलांग लगाई थी। अब मूडीज ने भारत का दर्जा बीएए-3 से बढ़ाकर बीएए-2 कर दिया है। ये महत्वपूर्ण सुधार है। मूडीज ए, बी और जंक में विभिन्न श्रेणियां देता है। ए और बी पॉजिटिव (सकारात्मक) रैंकिंग है। बीएए-3 पॉजिटिव का सबसे निचला पायदान है। ध्यानार्थ है कि वर्ष 2004 के बाद भारत की मूडीज रेटिंग में पहली बार सुधार हुआ है। इस एजेंसी ने इस निर्णय का कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद में हो रही बढ़ोतरी, नोटबंदी, जीएसटी, डूबते कर्ज से पैदा हुई बैंकों की समस्या को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों, आधार कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना इत्यादि को बताया है। जाहिर है, नरेंद्र मोदी सरकार के जिन फैसलों की विपक्ष अक्सर आलोचना करता है, उसे दुनिया दूसरी नजर से देख रही है। उसकी निगाह में ये अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए उठाए गए दूरगामी महत्व के कदम हैं, जिनसे देश को दीर्घकालिक लाभ होगा। इस बिंदु पर उल्लेखनीय है कि जिस समय नोटबंदी और जीएसटी से आमजन के लिए मुश्किलें खड़ी होने की बातें कही गईं, उसी वक्त भारत में विदेशी निवेश में लगातार वृद्धि हुई। यह भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व के यकीन का जीवंत प्रमाण है। अब विश्व बैंक के बाद मूडीज ने भी भारत के बारे में दुनिया में लगातार मजबूत हो रही आशाजनक दृष्टि की पुष्टि कर दी है। रेटिंग में सुधार का गहरा निहितार्थ होता है। किसी विदेशी या घरेलू कंपनी के लिए खुद ये आकलन करना कठिन होता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की मूलभूत स्थितियां कैसी हैं। ऐसे में वे अक्सर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के आकलन पर निर्भर करती हैं। ये रेटिंग एजेंसियां किसी देश की अर्थव्यवस्था के हर आयाम तथा संभावनाओं को देखते हुए उसकी श्रेणी तय करती हैं। अधिकांश निवेशक ऐसी रेटिंग के आधार पर अपनी निवेश योजनाएं एवं बाजार रणनीति बनाते हैं। चूंकि मूडीज ने भारत सरकार के आर्थिक और संस्थागत सुधारों का खास जिक्र किया है, तो उससे एनडीए सरकार की नीतियों और भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं में निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा। इससे यह संदेश जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था न सिर्फ स्थिर है, बल्कि लगातार अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ हो रही है।

- (नई दुनिया, 18 नवंबर)

सुधरता माहौल

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की संप्रभु बॉन्ड रेटिंग को बीएए3 से सुधार कर बीएए2 कर दिया है। यह निस्संदेह देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर है। सैद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो इस सुधार का अर्थ यह हुआ कि न केवल संप्रभु, बल्कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए भी विदेशी फंड जुटाना आसान होगा। देश की संप्रभु रेटिंग में सुधार के साथ एजेंसी ने कहा है कि ऐसा उन सुधारों के कारण किया गया जिन्हें सरकार ने अब तक अंजाम दिया है। उसका कहना है कि इन सुधारों से देश में कारोबारी माहौल सुधरेगा और मजबूत और स्थायी विकास की परिस्थितियां निर्मित होंगी। सरकार लंबे समय तक यह दलील देती रही है कि राजकोषीय समावेशन की उसकी प्रतिबद्धता और देश के स्थिर वृहद आर्थिक विकास संकेतकों को देखते हुए रेटिंग में सुधार आवश्यक हो चला है। कई पर्यवेक्षक कह रहे थे कि भारत, विकास की गति गंवा रहा है। ऐसे में यह भरोसा बहाली का एक मजबूत संकेत है। सरकार को विभिन्न नीतिगत बदलावों का श्रेय मिलना चाहिए, जिनके चलते रेटिंग में यह सुधार संभव हो सका।

- (बिजनेस स्टैंडर्ड, 19 नवंबर)

बड़ी कामयाबी

भारत की नुमाइंदगी के लिए न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी का हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एक बार फिर पहुंचना एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। उससे भी बड़ी बात यह कि यह ब्रिटेन जैसे एक सशक्त देश के लिए बड़ी हार है। इसका अहसास दुनिया के उन सर्वाधिक ताकतवर देशों को भी हो चुका है, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में वीटो के अधिकार से लैस हैं। भारत के लिए यह बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि दुनिया में आज भी विकासशील देश के रूप में पहचान के बावजूद उसने ब्रिटेन को एक ऐसे वैश्विक मंच पर पटखनी दी, जिसमें हमेशा से उसकी तूती बोलती आई थी। 1946 के बाद यह पहला मौका है जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पंद्रह जजों में ब्रिटेन का कोई जज नहीं है।

(जनसत्ता, २३ नवम्बर, २०१७)

स्फुट विचार...

यह सही है, काफी परिवर्तन हुआ है। साथ ही यह भी सही है कि अभी भी हमारे समाज से व्यक्तिगत विकृति तथा भेदभाव के कलंक को मिटाने के लिए बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। नारायण गुरु, महात्मा फुले और डा. भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तियों ने अपने जीवन से हमें जातिगत विकृति और विभेद से लड़ने का रास्ता दिखाया।

— कुशाभाऊ ठाकरे

हमारा राष्ट्र-जीवन विविधताओं से परिपूर्ण है। यहां अनेक भाषाएं हैं, अनेक सम्प्रदाय तथा मत-मतान्तर हैं, अनेक रहन-सहन के ढंग प्रचलित हैं, कला और साहित्य की अनेक विधियां और शैलियां विद्यमान हैं। ये विविधतायें हमारे जीवन की समृद्धि का परिचायक हैं। हमें विविधताओं में एकता की खोज करनी है और उसे सुदृढ़ बनाना है।

— अटल बिहारी वाजपेयी

प्रस्तुति: पंकज आनंद

हमारे सम्मानित आजीवन सदस्यगण

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री, भारत
श्री अमित शाह
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष
श्री अरुण जेटली
केंद्रीय वित्त एवं रक्षा मंत्री
श्री राधा मोहन सिंह
केंद्रीय कृषि मंत्री
श्री प्रकाश जावडेकर
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री
श्री जगत प्रकाश नड्डा
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
श्रीमती मेनका संजय गांधी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट राज्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय
केंद्रीय इस्पात राज्यमंत्री
श्री बाबुल सुप्रियो
केंद्रीय भारी उद्योग राज्यमंत्री
श्री मनोहर पर्रिकर
मुख्यमंत्री, गोवा

श्री भूपेन्द्र यादव, सांसद
भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री
श्री अरुण सिंह
भाजपा राष्ट्रीय महासचिव
श्री शांता कुमार, सांसद
पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश
श्री गोपाल नारायण सिंह
सांसद (राज्यसभा)
डॉ. गोकाराजू गंगा राजू
सांसद (लोकसभा)
श्री महेश पोद्दार
सांसद (राज्यसभा)
श्री अनिल शिरोले
सांसद (लोकसभा)
श्री मनोज राजोरिया
सांसद (लोकसभा)
श्री रवींद्र कुमार राय
सांसद (लोकसभा)
श्री दिलीप कुमार गांधी
सांसद (लोकसभा)
श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल
राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

सदस्यता प्रपत्र

नाम : ....

पूरा पता : ....

....

.... पिन : ....

दूरभाष : .... मोबाइल : (1).............................. (2)..............................

ईमेल : ....

सदस्यता						
	एक वर्ष	₹350/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी/अंग्रेजी)	₹3000/-	☐
	तीन वर्ष	₹1000/-	☐	आजीवन सदस्यता (हिन्दी+अंग्रेजी)	₹5000/-	☐

(भुगतान विवरण)

चैक/ड्राफ्ट क्र. :.............................. दिनांक :.............................. बैंक : ....

नोट : डीडी / चैक '**कमल संदेश**' के नाम देय होगा।
मनी आर्डर और नकद पूरे विवरण के साथ स्वीकार किए जाएंगे।

(हस्ताक्षर)

अपना डीडी/चेक निम्न पते पर भेजें
डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पीपी-66, सुब्रह्मण्य भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003
फोन: 011-23381428 फैक्स: 011-23387887 ईमेल: kamalsandesh@yahoo.co.in

कमल संदेश: राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

12वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, मनीला, फिलीपींस में वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मनीला, फिलीपींस में जापानी प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे से हाथ मिलाते प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

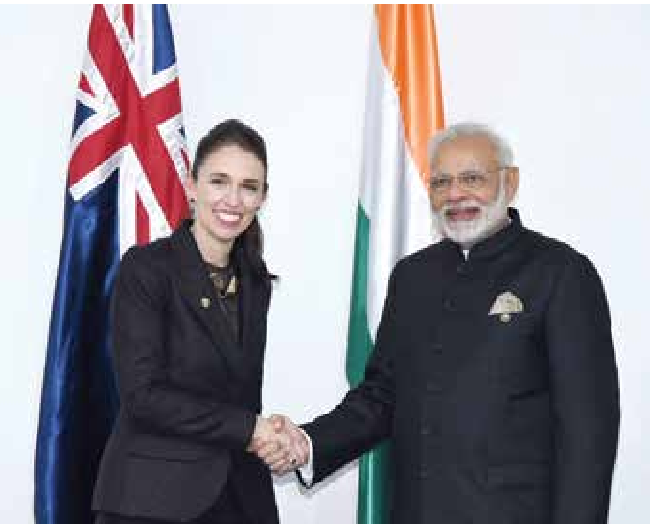

मनीला में न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न से मिलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मनीला, फिलीपींस में भारतीय समुदाय का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

मनीला, फिलीपींस में अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी

प्रेषण तिथि: (i) 1-2 चालू माह (ii) 16-17 चालू माह
डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली **"रजिस्टर्ड"**
36 पृष्ठ कवर सहित

आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953
डी.एल. (एस)-17/3264/2015-17
Licence to Post without Prepayment
Licence No. U(S)-41/2015-17